



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]
No. 34]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 1983/फाल्गुन 10, 1984
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 1983/PHALGUNA 10, 1984

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट प्रभाग)

बजट 1983-84

वित्त मंत्री का, दिनांक 28 फरवरी, 1983 का भाषण

नई दिल्ली, मार्च 1, 1983

भाग क

सं० एक० 15(1)—बी०(डी)/83:—(1) में वर्ष
1983-84 का बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ
है।

2. कुछ दिन पहले सदन के समक्ष वर्ष 1982-83
की जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई थी उसमें चालू वर्ष
के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों का विस्तृत
व्यापार दिया गया है। अतः मैं यहां आर्थिक स्थिति की समीक्षा
संक्षेप में ही करूंगा।

3. सूखे का वर्ष अर्थव्यवस्था के लिए सदा ही कठिनाई
का वर्ष होता है। सूखे के कारण कृषि के उत्पादन में जो

कमी होती है वह ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों को
भी प्रभावित करती है। हमारे किसान भाईयों की त्रय शक्ति
में गिरावट आ जाती है जिसका उद्योग पर अपस्फीतिकारी
प्रभाव पड़ता है। सूखे से विजली का उत्पादन भी प्रभावित
होता है और हमारी बाहरी अदायगियों पर भी उसका प्रति-
कूल प्रभाव पड़ता है। इससे साधनों में कमी हो जाती है
और साथ ही इसके कारण राहत व्यय में वृद्धि करने की
आवश्यकता हो जाती है। जो वर्ष समाप्त हो रहा है उसके
दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन को इसी
पृष्ठभूमि में देखना होगा। हम अपने उत्पादक ढांचे को
अत्यधिक क्षति पहुंचाए बिना उक्त स्थिति से उबर आए हैं
और हमने कीमतों की वृद्धि को नियंत्रण में रखने में उल्लेखनीय
सफलता प्राप्त की है, इसका श्रेय हमारी अर्थव्यवस्था की
सक्षमता को जाता है। इससे मांग को लगातार नियंत्रण में
रखने और पूर्ति का विवेकपूर्ण प्रबंध करने की हमारी नीतियों
की प्रभावोत्पादकता का भी पता चलता है।

4. यद्यपि इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पिछले
दो वर्षों की तुलना में कम होगी तथापि इन तीन वर्षों में
हम लगभग 5 प्रतिशत की औसत वृद्धि की दर प्राप्त कर
लेगे जो कि आयोजना के लिए निर्धारित हमारे लक्ष्य के

आम-गाम होगी। साथ ही, हम निवेश की गति को भी बरकरार रख सके हैं। दूसरे शब्दों में, हालांकि सूखे का प्रभाव गंभीर था, फिर भी मेरा विश्वास है कि हमने उससे विकास की गति को प्रभावित नहीं होने दिया है।

5 अब मैं, संक्षेप में, वर्ष 1982-83 की आर्थिक स्थिति की मुख्य बातों को दोहराता हूँ। बिन्दू-प्रति-बिन्दू आधार पर, जनवरी, 1983 के अन्तिम सप्ताह में थोक कीमतों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसकी तुलना में पिछले साल इसी समय वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 5.7 प्रतिशत थी। दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार, उपभोक्ता कीमतों के सूचक अंक में वृद्धि की वार्षिक दर 8 प्रतिशत रही जो दिसम्बर, 1981 की 12.7 प्रतिशत की दर से काफी कम थी। इस वर्ष मुद्रास्फीति की अपेक्षा-कुल कम दर, खासतौर से, इस बात को देखते हुए, उल्लेखनीय है कि मानसून में देरी हो जाने की वजह से उत्पन्न सट्टे-बाजी के दबावों के कारण, जून और जुलाई, 1982 में थोक कीमतें प्रति मास 2.4 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। किन्तु मांग और पूर्ति के प्रबंध की नीतियों के उपयुक्त सम्मिश्रण के द्वारा स्थिति पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया।

6 मौद्रिक नीति का लोचदार तरीके से पालन किया जाता रहा। संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा किन्तु साथ ही ऋण की उत्पादक आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयत्न किया जाता रहा। जहाँ तक पूर्ति का संबंध है, खाद्यान्नों का समय पर आयात करके उनका भंडार बनाने और उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई की गई। खाद्यान्नों की बमूली के प्रयत्नों को बढ़ाया गया ताकि खरीफ की पैदावार में होने वाली कमी का प्रभाव खाद्यान्नों के भंडार पर कम से कम पड़े। चीनी और खाद्य तेलों को भी अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया गया। इन कार्रवाइयों और अन्य पूर्ति प्रबंध संबंधी नीतियों के फलस्वरूप अगस्त, 1982 के बाद मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने में बहुत अधिक योगदान मिला।

7. जैसाकि मैंने इस सदन में पहले भी बहुत बार कहा है, कीमतों की स्थिति के बारे में हमारे लिए संतुष्ट होकर बैठ जाने की कोई गृहाहण नहीं है। संवेदनशील वस्तुओं के मामले में पूर्ति और मांग की स्थिति का संतुलन बढ़ा नाजुक होता है। हालांकि हमने सूखे के तात्कालिक प्रभाव को तो सफलतापूर्वक झेल लिया है, फिर भी हमें यह याद रखना होगा कि इसके प्रभाव संभवतः एक मौसम या एक वर्ष से अधिक की अवधि तक बने रहेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अब भी अनिश्चिततापूर्ण बनी हुई है और यदि विदेशों में पुनः मुद्रास्फीति की स्थिति, खासतौर से हमारे द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के मामले में उत्पन्न हुई तो इससे हमारी घरेलू कीमतों की स्थिति आसानी से बिगड़ जाती है। हमें समाज-विरोधी तत्वों, जमाखोरों और काला-बाजियों से भी सतर्क रहना होगा।

8. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, खरीफ के खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम होगा। किन्तु ऐसे संकेत मिले हैं कि रबी का उत्पादन संभवतः पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ अच्छा होगा। कपास की पैदावार लगभग गत वर्ष जितनी ही होगी, किन्तु गन्ने और जूट के उत्पादन में कुछ कमी होने की संभावना है। वर्ष 1982-83 के दौरान सिंचाई की धमना में वृद्धि करने का जो 23.5 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था उसके प्राप्त हो जाने की संभावना है। हालांकि कृषि क्षेत्र अब भी मौसम की अनिश्चितताओं से प्रभावित होता रहता है, किन्तु, दीर्घावधि में, हम पैदावार में पर्याप्त वृद्धि कर सके हैं और सूखे के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों को कम करने में सफल हुए हैं। हमसे यह प्रमाणित होता है कि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने, उर्वरकों और अधिक उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल करने, ऋण देने वाले तंत्र का विस्तार करने और प्रमुख फसलों के संबंध में उत्पादकों को उचित तथा लाभकारी कीमतें दिलवाने की जो हमारी कृषि नीति है वह मूलरूप से सही है।

9. वर्ष 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, संभवतः लगभग 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अप्रैल से दिसम्बर, 1982 की अवधि में, अतिमहत्वपूर्ण उद्योगों, जैसे कच्चा पेट्रोलियम (30.6 प्रतिशत) सीमेन्ट (10.2 प्रतिशत), उर्वरक (9.6 प्रतिशत) और बिजली (7.2 प्रतिशत) के उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। खासतौर से यह बात उत्साह-वर्द्धक है कि तापीय बिजली के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हुई है और तापीय बिजली संयंत्रों का संयंत्र भार अनुपात (प्लांट लोड फैक्टर) भी, जो अप्रैल-दिसम्बर, 1981 के दौरान 45.9 प्रतिशत था, बढ़ कर इस वर्ष 47.6 प्रतिशत हो गया है। आशा है कि चीनी का उत्पादन भी लगभग पिछले वर्ष के रिकार्ड स्तर के बराबर होगा। किन्तु औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की समग्र दर पर, सूती कपड़े और धागे (यार्न) के उत्पादन में भारी कमी हो जाने के कारण, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उद्योग के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मांग की शिथिलता के कारण या खासतौर से पत-बिजली पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में बिजली की मंगी जैसे कारणों से वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम रही है।

10. पिछले तीस वर्षों के दौरान, हमारे औद्योगिक ढांचे का विस्तार करने और उसमें विविधता लाने के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। निवेश संबंधी बातावरण बहुत अनुकूल है और वर्ष के दौरान पूजी निर्गम (केपिटल इश्यूज) एक रिकार्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। किन्तु, उत्पादन की वृद्धि की दर को तेजी से बढ़ाने और उसे बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है कि निगम क्षेत्र धमता के बेहतर उपयोग द्वारा और प्रदर्शनात्मक तथा निरर्थक व्यय में कृपायत करके अपनी बचतों की दर में वृद्धि करने की ओर अधिक ध्यान दे। यदि निवेश के लिए बढ़ती हुई धनराशियों की आवश्यकता

को पर्याप्त रूप से पूरा करना है तो निगम क्षेत्र को अपने आर्थिक साधन अधिक मात्रा में पैदा करने की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। धनराशियाँ उधार लेकर साधनों की अनुपूर्ति तो की जा सकती है लेकिन उधार की राशि निगम क्षेत्र की अपनी संचनों का रक्षान नहीं ले सकती।

11. यह भी आवश्यक है कि पहले किए गए पूजी-निवेश की उत्पादकता में वृद्धि की जाए और लागतों में कमी की जाए। अर्थव्यवस्था में पूजीगत लागत बढ़ गई है, और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो जाने से, जनता द्वारा किए गए पूजी-निवेश से मिलने वाले उस प्रतिफल में कमी हो जाती है जिसकी आशा वह उचित रूप से कर सकती है। सरकारी क्षेत्र के संबंध में, सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी कार्य-कुशलता पर पूरी तरह नजर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, सरकारी क्षेत्र के बहुत-से उद्योगों के कार्याचालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, हालांकि कुछ एककों को अब भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष के पहले नौ महीनों में सरकारी क्षेत्र के एककों को लगभग 360 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ जबकि पिछले साल की इसी अवधि में उन्हें 134 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

12. वित्तीय आधारभूत ढांचा बनाने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। बैंकिंग प्रणाली की व्याप्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, पहले से अधिक ग्रामीण बैंक खोल दिए गए हैं और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने अपना काम शुरू कर दिया है। इन सब से ग्रामीण क्षेत्र को संस्थागत ऋण का लाभ मिलने में और गह्रायता मिलेगी। बीमा की सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

13. पिछले कुछ वर्षों में, हमारे भुगतान-शेष की स्थिति एक चिन्ता का विषय बनी रही है। पिछले साल अपने बजट भाषण में मैंने यह बताया था कि सरकार ने मध्यमवर्धि में हमारे भुगतान-शेष की स्थिति को फिर से सक्षम बनाने के लिए क्या नीति अपनाई है। संक्षेप में, इस नीति के मुख्य तत्व हैं: तेल और उर्वरक जैसे अनिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन की गति को तेज करना, निर्यात बढ़ाना और भारतीय मूल के अनिवारियों द्वारा पूजी-निवेश और धन-प्रेषण के लिए उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस नीति को कार्यान्वित करने में हमें पर्याप्त सफलता मिली है।

14. देश में पेट्रोलियम और उर्वरकों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से हमें चालू वर्ष के दौरान इन मर्दों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में सहायता मिली है। इस्पात, अलौह धातुओं, और कई अन्य मर्दों का आयात भी पहले से कम हुआ है। हमारी आयात नीति का उद्देश्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को कच्चे माल और पूजीगत वस्तुओं को उद्योगतापूर्वक उपलब्ध कराने हुए आयात की वृद्धि को

कम करना है। जहां कहीं समुचित समझा गया है, स्वदेशी उद्योगों को और संरक्षण प्रदान करने के लिए टैरिफ नीतियों का कारगर ढांचा से इस्तेमाल किया जा रहा है।

15. निर्यातों में, जहां 1981-82 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 1982-83 के पहले नौ महीनों में 18 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार में बढ़ते हुए संरक्षणवाद, मांग में मंदी और लगभग गतिरोध से प्रभावित प्रतिकूल बाहरी वातावरण को देखते हुए यह एक अच्छी सफलता है। वर्ष 1982-83 में व्यापारिक घाटे के पहले से कम होने की संभावना है। हमारे प्रारक्षित मुद्रा भंडार में (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेन-देनों को शामिल न करते हुए) कमी होने की दर भी कम हो गई है और इन वित्तीय वर्ष में जनवरी, 1983 के अंत तक यह दर औसत रूप से 91 करोड़ रुपये प्रतिमास रही है जबकि 1981-82 के दौरान 175 करोड़ रुपये प्रतिमास रही थी।

16. किन्तु, हमारे भुगतान-शेष के समायोजन का कार्य औद्योगिक देशों में आर्थिक सहयोग के लिए राजनैतिक संकल्प के अभाव से उत्पन्न अननुकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण और कठिन हो गया है। यह आवश्यक है कि विकास-शील और अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर, हम अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक प्रणाली में बुनियादी सुधार करने के लिए अपने प्रयत्नों को जारी रखें। भारत कारियायती प्राप्तियों के अपने हिस्से में होने वाली असमानुपातिक कटौती का भी बोझ उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में, कुछ मात्रा में वाणिज्यिक ऋणों का सहारा तो लेना ही होगा, किन्तु हमें चालू खाते के घाटे की वित्त-व्यवस्था करने के उपाय के रूप में इस साधन पर निर्भर रहने में अत्यन्त सावधानी बरतनी होगी।

17. सम्मानित सदस्य इस क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिति और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के कारण हमारे बढ़ते हुए बोझ में अवगत हैं। जब राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो तो कोई भी कुर्बानी ज्यादा नहीं होती। साथ ही, हम विकास के कार्य में भी ढील नहीं दे सकते, भले ही कार्य कितना ही भारी क्यों न हो, क्योंकि अन्तर्तांगत्वा राष्ट्र की सुरक्षा भी आर्थिक शक्ति पर ही निर्भर करती है। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि साधन संबंधी स्थिति कठिन होने के बावजूद हम 1982-83 के दौरान आयोजना के परिदृश्य से पर्याप्त वृद्धि कर सके हैं। साधनों के उपयोग में और अधिक मितव्ययता और कुशलता की आवश्यकता पर जितना बल दिया जाए, थोड़ा होगा। हमें एक गैर-मुद्रास्फीतिकारी तरीके से, अतिरिक्त साधन जुटाने के कार्य को आगे भी चालू रखना होगा।

18. राष्ट्र के साधनों का उपयोग करने के कार्य में राजकोपीय नीति को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। कर की दरों में समुचित समायोजनों के अलावा, आवश्यक प्रशासनिक और निधिक उपाय भी किए जा

है ताकि यह मुनिश्चित हो सके कि समाज के सभी वर्ग तत्परतापूर्वक अपने कर अदा करें। यह सरकार करों के परिवर्जन और अपवंचन के सभी रास्तों को बंद करने और आर्थिक अपराधों के विरुद्ध अपने अभियान को जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है।

19. हमारे लोगों के जीवन-यापन के स्तर को बचतों और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करके ही ऊंचा उठाया जा सकता है। हमें यह साभार स्वीकार करना होगा कि भारत के लोगों ने बचत के ऐसे स्तर कायम किए हैं जो हमारे जैसे कम आय वाले देश के लिए एक असाधारण बात है। किन्तु यह आवश्यक है कि इन बचतों को ऐसी परिस्थितियों में लगाया जाए जिनसे उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो और जो जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएं।

20. पिछले तीन वर्षों के दौरान, बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। वित्तीय परि-सम्पत्तियों के रूप में बचतों पर आकर्षक प्रतिफल देने के लिए ब्याज दरों के ढांचे और राजकोषीय तन्त्र का उपयोग किया गया है। पंचवर्षीय बैंक जमा राशियों पर ब्याज की दर को बढ़ाने के निर्णय के अनुरूप ही, जो गत वर्ष अक्टूबर में घोषित किया गया था, यह निर्णय लिया गया है कि पंचवर्षीय डाकघर, सावधि जमा राशियों और आबर्ती जमा राशियों पर ब्याज की दर को 10.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया जाए। इसी प्रकार, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि कर्मचारी भविष्य निधि की विशेष जमा राशियों और अन्य गैर-सरकारी भविष्य, उपदान और अधिवर्षता निधियों की जमा राशियां पर ब्याज की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। इन जमा राशियों पर ब्याज की दर में वृद्धि कर दिए जाने से कामगारों और छोटे बचतकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

21. मैं लोक भविष्य निधि योजना को भी उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूँ जोकि अपना घन्धा करने वालों और अन्य लोगों में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है। अभिदाताओं को अपने खाते 15 वर्ष के बाद भी चालू रखने की अनुमति होगी। वार्षिक अभिदान की सीमा को भी बढ़ाकर 40,000 रुपए किया जा रहा है।

22. पिछले दो वर्षों में मौद्रिक और आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अभिमां के ब्याज की दरों की समीक्षा की है। ब्याज की अधिकतम दर को 19.5 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निश्चय किया गया है। कृषि, लघु उद्योग और निर्यात के फायदे के लिए ब्याज की दरों के ढांचे में भी नीचे की और समायोजन किए जा रहे हैं। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से घोषणा की जा रही है।

23. सरकार ने भारतीय मूल के अनिवासियों द्वारा पूंजीनिवेश और धन प्रेषण को आकर्षित करने के लिए उदार प्रोत्साहन दिए हैं। अनुभव के आधार पर, यह निश्चय किया गया है कि अनिवासियों को उपलब्ध सुविधाओं को और बढ़ाया जाए, पिछले साल मैंने अनिवासियों द्वारा 6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों में, जिन पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दिया जाता है, किए गए अभिदानों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण रियायतों की घोषणा की थी। उनको प्राप्ति में और वृद्धि करने के उद्देश्य से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इन बचत-पत्रों पर, यदि वे विदेशी मुद्रा से खरीदे गए हों तो 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जाए। मेरे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि सदन मुझसे इस बात में सहमत होगा कि हमारी नीतियों का ढांचा अनिवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है और हम आशा कर सकते हैं कि इससे अनिवासियों और इस देश के बीच विद्यमान संबंध और मजबूत होंगे।

24. अब मैं 1982-83 के संशोधित अनुमानों और 1983-84 के बजट अनुमानों की ओर आता हूँ।

1982-83 के संशोधित अनुमान

25. वर्ष 1982-83 में कुल व्यय के लिए 20,219 करोड़ रुपए का बजट अनुमान था, जिसमें से 11,345 करोड़ रुपए आयोजना व्यय के लिए और 17,874 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न व्यय के लिए थे। जैसे जैसे साल बीतता गया, यह स्पष्ट होता गया कि हमें इन दोनों प्रकार के व्ययों को बढ़ाना होगा। दैवी विपत्तियों के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दबावों के बावजूद, हमारा यह प्रयास रहा है कि दीर्घाधिक विकास के परिदृश्य में कोई कमी न की जाए। इसलिए मेरी एक उच्चतम प्राथमिकता यह थी कि आयोजना को बचाया जाए और इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के संशोधित अनुमान, मूल बजट में निर्धारित अनुमानों से, 603 करोड़ रुपए ज्यादा है।

26. रेलवे के आयोजना परिव्यय में 195 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिसमें 105 करोड़ रुपए की वजटीय सहायता होगी। विद्युत क्षेत्र की वजटीय सहायता को 62 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, जबकि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को दी जाने वाली सहायता में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। परिवार कल्याण की योजनाओं के परिव्यय में 50 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण जलपूर्ति, कृषि और सहकारिता की आयोजना-व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया गया है जबकि डाक-तार आयोजना की वजटीय सहायता में 75 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, डाक-तार के मामले में यह वृद्धि उनके आन्तरिक साधनों में कमी हो जाने के कारण की गई है। जहां एक ओर ये वृद्धियां की गई हैं वहां दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों के आयोजना व्यय के बजट अनुमानों में कुछ कटौती किए जाने की सम्भावना है। कुल मिलाकर, केन्द्रीय आयोजना के लिए वजटीय सहायता

में 262 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाने का अनुमान है और वही इस प्रकार 7,605 करोड़ रुपए की हो जाएगी।

27. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता में भी 380 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है। इसमें से 350 करोड़ रुपए की राशि उन राज्यों को अनिश्चित अग्रिम आयोजना सहायता देने के लिए है जो सूखे से प्रभावित हुए हैं।

28. चालू वर्ष के दौरान आयोजना-भित्त व्यय में भी कई कारणों से वृद्धि होगी। राज्यों को दिए जाने वाले आयोजना-भित्त अनुदानों में 214 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी जिसका मुख्य कारण यह है कि बाढ़ों, चक्रवातों और अन्य देवी विपत्तियों से प्रभावित राज्यों को 147 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई है। इसी प्रकार, अल्पवृत्तों के संग्रह में वृद्धि हो जाने कारण, इस संबंध में राज्यों को दिए जाने वाले आयोजना-भित्त ऋणों में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। कृषि निविष्टियों (इनपुट) के लिए दिए जाने वाले आयोजना-भित्त ऋणों में भी 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। स्वदेशी उर्वरकों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की राशि भी 200 करोड़ रुपए अधिक होगी। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के लिए 209 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋणों की आवश्यकता है ताकि वे उपक्रम अपनी नकद हानियों और सरकार के प्रति ब्याज तथा वापसी अदायगी की देनदारियों को पूरा कर सकें।

29. रक्षा व्यय के लिए की गई व्यवस्था में भी 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। रुपए व्यापार करारों के अंतर्गत किए जाने वाले व्यापार में अल्पकालिक असंतुलन को ठीक करने के लिए तकनीकी ऋणों की व्यवस्था का 80 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1280 करोड़ रुपए करना पड़ा है: तकनीकी ऋणों में वृद्धि अस्थायी और आपदादिक परिस्थितियों के कारण हुई है, और वर्ष के दौरान इसका रूप काफी हद तक पलट जाएगा। सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि विश्वस्तरीय कमजोर मांग के वर्ष में, समाजवादी देशों के साथ हमारे पुराने व्यापारिक संबंधों ने हमारे निर्यात के क्षेत्र को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

30. राज्यों को दिए जाने वाले 1,743 करोड़ रुपए के ऋण को शामिल न करते हुए, जिसका उल्लेख में बाद में करूंगा, कुल आयोजना-भित्त व्यय संभवतः 17,874 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,511 करोड़ रुपए हो जाएगा।

31. जहां तक प्राप्तियों का संबंध है, जैसाकि मैंने शुरू में कहा था, सूखे के कारण अर्थव्यवस्था के आय और साधन आधार पर अनिवार्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद आय-कर और सीमा-शुल्क की प्राप्तियों के बजट अनुमान पूरे हो जाने की आशा है। किन्तु संघ-उत्पाद-शुल्कों से होने वाली प्राप्तियों में शायद 220 करोड़ रुपए की कमी रहेगी। इसका एक कारण तो यह है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई

है और दूसरे, विचाराधीन मुकदमों के कारण भी कुछ राजस्व की प्राप्ति रुक गई है। निगम करों की प्राप्ति में भी कुछ कमी रहने की संभावना है। करों में राज्यों के हिस्से की अदायगी करने के बाद, केन्द्र का निवल कर-राजस्व, अनुमानतः 13,271 करोड़ रुपए का होगा जब कि बजट अनुमान 13,362 करोड़ रुपए का था।

32. किन्तु कर-भित्त राजस्व में 613 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की आशा है, जिसके मुख्य कारण ये हैं कि रेलवे द्वारा अपेक्षाकृत अधिक लाभांश दिया गया है, मरकारी क्षेत्र के कुछ एककों से अधिक प्राप्तियां हुई हैं, भारतीय डेरी निगम से उसे पहले उपहार में दी गई सामग्री का मूल्य वसूल हुआ है और विदेशी अनुदान अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त हुए हैं।

33. अनुमान है कि पूंजीगत प्राप्तियों में भी वृद्धि होगी, अर्थात् इनकी राशि 10,249 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,446 करोड़ रुपए हो जाएगी। बाजार ऋणों से 3,800 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान में इनकी राशि 3,200 करोड़ रुपए रखी गई थी। जैसा कि पहले कहा गया है, तकनीकी ऋणों से भी 90 करोड़ रुपए की बजाय 1,080 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। अल्प वृत्तों से होने वाली प्राप्तियों में 150 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है।

34. इस प्रकार कुल प्राप्तियों की राशि 27,844 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,563 करोड़ रुपए हो जाएगी।

35. प्राप्तियों और व्यय में उपर्युक्त और अन्य घटवृद्ध को हिसाब में लेने पर, अब अनुमान है कि चालू वर्ष में बजट का घाटा 1,935 करोड़ रुपए का होगा। इसमें राज्यों को दी जाने वाली 1,743 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सहायता शामिल नहीं की गई है जिसका चालू वर्ष में कोई आर्थिक अंतर नहीं होगा। चालू वर्ष में बजट अनुमानों की अपेक्षा हुए अधिक घाटे का अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में व्याप्त कमजोर मांग की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसका अर्थव्यवस्था पर कोई अस्थिरताकारी असर नहीं हुआ है, यह बात हाल के महीनों में कीमतों की स्थिति से प्रमाणित होती है।

1983-84 के बजट अनुमान

36. अध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष के बजट को तैयार करने में मेरा उद्देश्य यह रहा है कि आयोजना परिव्यय में भारी वृद्धि के लिए व्यवस्था की जाए ताकि विकास की गति जिसे हमने अध्यक्षसमक्ष प्राप्त किया है, धीमी न होने पाए। मुझे भली भांति मालूम है कि इतनी वृद्धि कर देने पर भी विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को पूर्णतः पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वे कितनी ही अधिक जरूरी क्यों न प्रतीत होती हों। अतः विभिन्न उद्देश्यों

क्षेत्रों के बीच प्राथमिकताओं के क्रम को फिर से निर्धारित करना जरूरी हो गया है।

37. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय आयोजना के परिव्यय को बढ़ाकर 1983-84 में 13,870 करोड़ रुपए कर दिया जाए; इसमें 300 करोड़ रुपए का एक विशेष आबंटन शामिल है जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की यह राशि 1982-83 के बजट अनुमानों में निर्धारित 11,000 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय से 26.1 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1982-83 के बजट में की गई 27.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद इस प्रस्तावित वृद्धि से हम अर्थव्यवस्था के अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए चालू किए गए कार्यक्रमों को भी विशेष बल प्रदान कर सकेंगे। केन्द्रीय आयोजना को 8,390 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से और 5,480 करोड़ रुपए के आंतरिक तथा बजट बाह्य साधनों से वित्तपोषित किया जाएगा।

38. सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि बहुत-से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कुछ समय से भारी दबाव पड़ रहा है। यद्यपि राजकोपीय अनुशासन की आवश्यकता पर जितना जोर दिया जाए कम है, तथापि केन्द्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना भी रहा है कि साधनों की तंगी के बावजूद, राज्यों की आयोजनाओं में भी उचित मात्रा में वृद्धि हो। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि जून, 1982 में, मैंने यह निश्चय किया था कि 1,743 करोड़ रुपए का मध्य मावधिक ऋण देकर राज्यों के पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम घाटों को माफ कर दिया जाए। मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि राज्य अपने वित्त का पुनः समायोजन कर सकें और अपनी आयोजनाओं में पर्याप्त पूजी लगा सकें। चालू वर्ष में, केन्द्र ने राज्यों को सूखे और बाढ़ में राहत पहुंचाने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इसके अलावा, हमने राज्यों को अगले दो वर्षों में मूलतः अनुमोदित मात्रा में से उपलब्ध शेष राशि के अतिरिक्त 1,650 करोड़ रुपए की और केन्द्रीय सहायता देने का निश्चय किया है। इससे राज्यों के आयोजना संबंधी साधन बढ़ जाएंगे। राज्यों ने भी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है और वे अपने साधन जुटाने के प्रयत्नों में वृद्धि करने के लिए राजी हो गए हैं।

39. वर्ष 1983-84 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल आयोजना परिव्यय अब 11,625 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह राशि 1982-83 में अन्तिम रूप से अनुमोदित 9,989 करोड़ रुपए के परिव्यय से 16.4 प्रतिशत अधिक है; और यह वृद्धि चालू आयोजना अवधि में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 4,462 करोड़ रुपए की होगी।

40. वर्ष 1983-84 के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आयोजना परिव्यय की राशि, कुल मिलाकर, 25,495 करोड़ रुपए की होगी जो कि 1982-83 में अन्तिम रूप से अनुमोदित परिव्यय की 20,989 करोड़ रुपए की तुलना में 21.5 प्रतिशत अधिक है।

41. वर्ष 1983-84 की आयोजना बनाते समय हमने सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखा है कि उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को अधिकतम समर्थन दिया जाए जिनसे अर्थव्यवस्था को और खासतौर से समाज के कमजोर वर्गों को तत्काल लाभ मिल सकता हो। नए 20-सूत्री कार्यक्रम के परिव्यय को बढ़ा दिया गया है, और उन कार्यक्रमों को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से गरीब लोगों को फायदा पहुंचता हो।

42. मैंने अगले वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष रूप से, 13,570 करोड़ रुपए के अलावा, 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है। यह कुछ अपारम्परिक-सा कदम है। यह राशि राज्यों को विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनके बेहतर कार्य निष्पादन के आधार पर अनुदानों के रूप में दी जाएगी। इन कार्यक्रमों से समाज के कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचेगा और राज्यों के बिजली बोर्डों के कार्यचालन में सुधार होगा इसके लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है और जहाँ कहीं उपयुक्त होगा, इस संबंध में जारी किए जाने वाले मार्ग-निर्देशों में, राज्यों द्वारा समानुपातिक अंशदान किए जाने का उपबंध किया जाएगा।

43. इस आबंटन में से मैं 125 करोड़ रुपए छोटे और भीमान्ति कसानों को उनकी जमीन की उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता देने के लिए निर्धारित कर रहा हूँ। मेरे साथी कृषि मंत्री जी इस योजना के ध्यौरे घोषित करेंगे।

44. 125 करोड़ रुपए की एक अन्य राशि राज्यों को उच्च प्राथमिकता वाले विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर वितरित की जाएगी। इनके बारे में घोषणा सरकार द्वारा बाद में की जाएगी। इन प्रयोजनों के लिए सहायता उन्ही राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो अपनी अनुमोदित आयोजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों से भी ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता दिखाएंगे।

45. मैं एक बार पहले भी मौजूदा पूजी-निवेशों से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के महत्त्व पर जोर दे चुका हूँ। तापीय बिजली धरों में संयंत्र भार अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता पर जितना बल दिया जाए थोड़ा है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 300 करोड़ रुपए में से बाकी 50 करोड़ रुपए राज्यों के बिजली बोर्डों को उनके बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के हेतु अलग

रख दिए जाएं। अधिकांश राज्यों के विजली बोर्डों ने 1975-77 के दौरान अपने शिखर संयंत्र भार अनुपात प्राप्त कर लिए थे। दुर्भाग्यवश, उनका हाथ का कार्य-निष्पादन उन स्तरों से बहुत नीचा रहा है। मुझे आशा है कि इस प्रोत्साहन ने राज्यों के विजली बोर्ड अपने पूर्ववर्ती शिखर स्तरों तक पहुंचने, बल्कि उनसे भी ऊपर निकल जाने के लिए प्रेरित होंगे।

46. अपर्युक्त विशेष आवंटन के अलावा, 1983-84 की केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए 2,747 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो चालू वर्ष की आयोजना के परिव्यय से 26.8 प्रतिशत अधिक है। राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के 1983-84 के अनुमोदित आयोजना परिव्यय में इन योजनाओं के लिए 7,332 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सम्मानित सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि इस प्रकार अगले वर्ष 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था होगी।

47. अगले वर्ष के कार्यक्रम में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र का कुल परिव्यय 608 करोड़ रुपए का होगा। इसमें 200 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के लिए है। वर्ष 1983-84 में दो प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाएंगे; एक तेजहन विकास के लिए और दूसरा बरानी भूमि में खेती के लिए होगा। ये दोनों कार्यक्रम 20-सूत्री कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के अनुमोदित आयोजना परिव्यय में कृषि कार्यक्रमों के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। मिर्चाई और बाढ़-नियंत्रण के परिव्यय को भी बढ़ा कर केन्द्रीय आयोजना में 116 करोड़ रुपए और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की आयोजनाओं में 2,404 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

48. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं का परिव्यय 1983-84 में 480 करोड़ रुपए होगा, जबकि उनपर 1982-83 में 419 करोड़ रुपए का व्यय होने की सम्भावना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग तीस लाख परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में 3,500 लाख कार्य दिवसों के बराबर रोजगार उत्पन्न होगा। इन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों द्वारा समानुपातिक आधार पर व्यवस्था की जाएगी।

49. सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि सरकार ने सभी सम्भाव्य ग्रामों में पैय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने का एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 1982-83 के आयोजना परिव्यय में केन्द्र

द्वारा त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के लिए 127.5 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने की परिकल्पना की गई थी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति को देखते हुए, अब इस परिव्यय को बढ़ा कर 155 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 1983-84 में इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षाकृत काफी अधिक अर्थात् 200 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राज्य अपनी ओर से 319 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करेंगे और आशा है कि 1983-84 में 48,000 और गांव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएंगे।

50. बच्चों की भलाई के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा है। अब छठी आयोजना के लिए जो ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार इस योजना को, जिसे अब तक 620 परियोजनाओं में लागू किया जा चुका है, 1983-84 में 200 और परियोजनाओं में शुरू करने का प्रस्ताव है। समाज कल्याण विभाग की 60 करोड़ रुपए की कुल व्यवस्था का आधे से अधिक भाग इस योजना के लिए है।

51. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भलाई के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, 1983-84 की केन्द्रीय आयोजना में पहले से अधिक अर्थात् 176 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

52. वर्ष 1983-84 में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का नए उत्साह के साथ कार्यान्वित किया जाएगा और इन्हें 170 लाख व्यक्तियों पर लागू किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जा रही है।

53. छठी आयोजना में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की गति को बढ़ाने पर काफी जोर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए, जिसमें पेट्रोलियम, विद्युत और कोयला शामिल हैं, कुल 5,014 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के 36 प्रतिशत से भी अधिक है। आशा है कि कच्चे तेल का उत्पादन इस वर्ष 210 लाख मेट्रिक टन होगा और 1983-84 में और बढ़ कर लगभग 260 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा।

54. परमाणु ऊर्जा और कोयले के अन्तर्गत विद्युत विकास के लिए नियत राशि को शामिल करके, 1983-84 में केन्द्रीय आयोजना में विभिन्न विद्युत कार्यक्रमों का कुल परिव्यय 1,222 करोड़ रुपए होगा, जो 1982-83 के परिव्यय से 31.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता में 1,050 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है जो चालू वर्ष के लक्ष्य से दुगुना है।

55. वर्ष 1983-84 में कोयला क्षेत्र का परिव्यय, जिसमें लिग्नाइट का परिव्यय भी शामिल है, 946 करोड़ रुपए का होगा। कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 1,420 लाख मेट्रिक टन रखा गया है, जो चालू वर्ष के उत्पादन से 90 लाख मेट्रिक टन अधिक है।

56. वर्ष 1983-84 की आयोजना में इस्पात विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 820 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1983-84 में खान विभाग का आयोजना परिव्यय बढ़ा कर 494 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि चालू वर्ष का अनुमोदित आयोजना परिव्यय 292 करोड़ रुपए का था। इसमें उड़ीसा एल्युमिनियम परियोजना के लिए रखे गए 365 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

57. अनुमान है कि 1983-84 में रेलवे का राजस्व यातायात 2,410 लाख मेट्रिक टन होगा, इस प्रकार इसमें 1982-83 के संभावित यातायात की तुलना में 6 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि होगी। वर्ष 1983-84 में रेलवे का आयोजना परिव्यय 1,342 करोड़ रुपए का होगा।

58. अनुमान है कि पत्तनों पर निपटाया जाने वाला यातायात 1983-84 में बढ़ कर 1,050 लाख मेट्रिक टन का होगा, जबकि 1982-83 में 950 लाख मेट्रिक टन का यातायात निपटाए जाने की सम्भावना है। वर्ष 1983-84 में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के लिए कुल 558 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें न्हावा शेवा परियोजना के लिए की गई 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था और राज्यों के सड़क परिवहन निगमों में निवेश के लिए की गई 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

59. रसायन और उर्वरक मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 429 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें 260 करोड़ रुपए धान वैश्व उर्वरक परियोजना के लिए हैं। हजारा उर्वरक परियोजना के लिए 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

60. उद्योग मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए, चालू वर्ष की 480 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तुलना में, 1983-84 में कुल 549 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें से 173 करोड़ रुपए की व्यवस्था लघु उद्योगों के लिए है, जिनमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग और नारियल जटा उद्योग भी शामिल हैं।

61. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विभिन्न आयोजना कार्यक्रमों के लिए 1983-84 में 72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने हाल में अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत विभाग की अलग से स्थापना की है। इस विभाग द्वारा 1983-84 में जो कार्यक्रम हाथ में लिए जाने हैं उनमें, अन्य बातों के अलावा, परिवारिक आकार के 75,000 बायो-गैस एककों और 100 सामुदायिक बायो-गैस एककों की स्थापना करना भी शामिल है। इस विभाग के लिए 1983-84 की आयोजना में 30 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें बायो-गैस कार्यक्रम के लिए की गई 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है।

62. अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रयत्न यह रहा है कि आयोजना निम्न व्यय को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण

क्षेत्रों में वृद्धि होनी अनिवार्य है। देश की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए, रक्षा के लिए चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 5,350 करोड़ रुपए की तुलना में अगले वर्ष के बजट में 5,971 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ऋणों में, जिनका इस्तेमाल मुख्यतः विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वृद्धि होने और इसके अलावा ऋण-लागत के बढ़ जाने के कारण ब्याज की अदायगी के लिए 4,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में इसके लिए 3,950 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खाद्यान्न सम्बन्धी आर्थिक सहायता (मसिन्डी) के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 90 करोड़ रुपए अधिक है। अनुमान है कि देश में उत्पादित उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अगले वर्ष 700 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि चालू वर्ष में 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। निर्यात के लिए मंडी विकास सहायता और नकद क्षतिपूर्ति सहायता लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

63. अगले वर्ष रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत तकनीकी ऋणों के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि चालू वर्ष में 1,280 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों, पेंशनों और अन्य राहतों की अदायगी करने के लिए 300 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि की व्यवस्था की जा रही है।

64. सदन को याद होगा कि पिछले वर्ष मैंने कम पेंशन पाने वाले व्यक्तियों लिए कतिपय लाभों में वृद्धि करने की घोषणा की थी। मेरा इस श्रेणी के पेंशनभोगियों को कुछ अतिरिक्त राहत देने का प्रस्ताव है। पहली अप्रैल, 1983 से मंहगाई राहत सहित पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ा कर 160 रुपए मासिक और परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि, जिसमें मंहगाई राहत भी शामिल है, बढ़ा कर 150 रुपए मासिक कर दी जाएगी।

65. अनुमान है कि 1983-84 में कुल आयोजना-निम्न व्यय 21,984 करोड़ रुपए होगा, जबकि 1982-83 के संशोधित अनुमानों में 20,511 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

66. इस अवसर पर मैं सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित एक मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। कर्मचारियों ने कुछ समय पहले सुझाव दिया था कि सरकार वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के लिए एक वेतन निकाय नियुक्त करे। तीसरा वेतन आयोग अप्रैल, 1970 में नियुक्त किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट 1973 में दी थी। तबसे, इन वर्षों के दौरान स्थिति में कई प्रकार के परिवर्तन हो गए हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई है। परस्पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की

उपलब्धियों की अपेक्षितताओं (रिलेटिविटी) और अन्य कर्मचारियों की तुलना में उनको उपाधियों की अपेक्षितताओं में भी परिवर्तन हो गए हैं। उदाहरण के रूप में, कई राज्य सरकारों ने वेतन समितियों अथवा वेतन आयोगों के जरिए अपने कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य लाभों में काफी अधिक संशोधन कर दिए हैं। मेरा विचार है कि अब चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग नियुक्त करना उपयुक्त होगा। वेतन आयोग के विचारणीय विषयों को तय करने से पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा। आयोग के सदस्यों और विचारणीय विषयों की घोषणा यथासंभव शीघ्र कर दी जाएगी।

57. जहां तक 1983-84 में होने वाली प्राप्तियों का संबंध है, कराधान की मौजूदा दरों पर 19,964 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 17,910 करोड़ रुपए के हैं। अनुमान है कि 1983-84 में करों में राज्यों का हिस्सा 5,088 करोड़ रुपए का होगा जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष में यह 4,639 करोड़ रुपए का है। इस प्रकार केन्द्र का निवल कर-राजस्व, चालू वर्ष के 13,271 करोड़ रुपए की तुलना में, 14,876 करोड़ रुपए का होगा।

68. बाजार ऋणों में, चालू वर्ष के 3,800 करोड़ रुपए की तुलना में, 4,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। अगले वर्ष तकनीकी ऋणों की बसूलियां कम होंगी क्योंकि अदायगियां भी कम की जाएंगी। अगले वर्ष अल्प बचत संग्रह में, इस वर्ष की 1,550 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में, 1,700 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। ऋणों की वापसी अदायगियों की रकमों को घटाने के बाद, 1,940 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष के दौरान इसकी राशि 1,724 करोड़ रुपए की थी।

69. प्राप्तियों में होने वाली इन घटबढ़ों और अन्य परिवर्तनों की हिमाब में लेने के बाद, 1983-84 में कुल 32,586 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। इन प्राप्तियों में रेल किरायों और भाड़ों की दरों तथा डाक-तार की शुल्क दरों में होने वाले परिवर्तनों तथा आयकर दाताओं के लिए अनिवार्य जमा यांजना की 31 मार्च, 1983 के बाद जारी रखने के परिणाम शामिल हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। कुल व्यय 34,836 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार, कराधान की मौजूदा दरों पर बजट में कुल मिलाकर 2,250 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

भाग II

70. अध्यक्ष महोदय मैं बजटीय परिणामों की इस समीक्षा की पृष्ठभूमि में सम्मानित सदस्यों के सम्मुख अपने बजट प्रस्ताव रख रहा हूं। बजट राजस्व जुटाने अथवा परिणामों की वित्त-व्यवस्था करने का साधन ही नहीं, बल्कि

इससे कुछ अधिक भी है। यह किसी आयोजित अर्थव्यवस्था में उपयुक्त वित्तीय और राजकोषीय नीतियों के द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने और विकास की गति को बरकरार रखने का एक सशक्त उपकरण है। इसलिए मैं सम्मानित सदस्यों को अपने बजट के दर्शन से अवगत कराना चाहूंगा। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उत्पादक शक्तियों को मजबूत बनाना, मुद्रास्फीति को कड़ाई से काबू में रखना, वैयक्तिक और निगमित दोनों क्षेत्रों में बचतों को प्रोत्साहन देना और आवश्यक पूंजी-निवेश को बढ़ावा देना है। बचतों को प्रोत्साहन देने का परिणाम उपभोग को निरुत्साहित करना है। हमारे जैसे समाज में वैयक्तिक अथवा निगम स्तर पर प्रदर्शनात्मक उपभोग का कोई स्थान नहीं है। मैंने इस अवसर का उपयोग कर-संबन्धी कानूनों में दिए गए कतिपय प्रोत्साहनों और रियायतों की समीक्षा करने और जहां उचित था वहां उन्हें संशोधित करने के लिए भी किया है। हम आज जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं, उसमें यह जरूरी है कि बजट से विदेशी भुगतानों की स्थिति को यथासंभव शीघ्र सक्षम बनाने की परमावश्यकता परिलक्षित होनी चाहिए और इसलिए बजट के द्वारा राजकोषीय साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने और आयात में कमी करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

71. इस सम्पूर्ण परिधि में रहते हुए, मेरा उद्देश्य यह रहा है कि अगले वर्ष बजट के घाटे को अपेक्षाकृत कम रखा जाए। हालांकि अतिरिक्त साधन जुटाना जरूरी है, फिर भी मैंने यह काम गैर-मुद्रास्फीतिकारी तरीके से और कम तथा भव्य आय वाले वर्गों पर अतिरिक्त भार डाले बिना करने का प्रयत्न किया है।

72. मैं सबसे पहले निगम-मिश्र आय-करों के क्षेत्र से संबन्धित अपने प्रस्तावों को लूंगा। मेरा उद्देश्य आय-खंडों के निचले हिस्से पर और विशेषकर वेतनभोगी करदाता को कुछ राहत प्रदान करना है। इसके साथ-साथ मेरा यह प्रयास भी रहा है कि उपभोग को निरुत्साहित करके बचतों को बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मैं बचतों से संबन्धित छूटों को अधिक उदार बनाने की व्यवस्था कर रहा हूं।

73. मैं अपने विनिष्ट प्रस्तावों की शुरुआत एक अग्रिम प्रस्ताव से करूंगा। मैं निगम-मिश्र करदाताओं पर लगने वाले आय-कर के अधिभार (सरचार्ज) की मौजूदा 10 प्रतिशत की दर को बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 47 करोड़ रुपए और वर्ष 1983-84 में 37.6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। यह मांग राजस्व केन्द्र को जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के कारण केन्द्र पर पड़ने वाले भार में हुई वृद्धि को देखते हुए, सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह उपाय न्यायोचित है।

74. और अब सुखद समाचार सुनि। वेतनभोगी करदाताओं को राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मानक कटौती की 5000 रुपए की मौजूदा उच्चतम सीमा को बढ़ा कर 6000 रुपए कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप राजस्व में एक पूरे वर्ष में 19 करोड़ रुपए और वर्ष 1983-84 में 15.2 करोड़ रुपए की हानि होगी।

75. हाल के वर्षों में हमने आय-कर के सम्बन्ध में छूट की सीमाओं को बढ़ाया है। लेकिन मुझे कुछ श्रौचित्य के साथ यह बताया गया है कि प्रारम्भिक आय-खंड के मामले में कर की दर कुछ ऊँची है। तदनुसार, मैं प्रारम्भिक आय-खंड को विभाजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब 15,001 रुपए से 20,000 रुपए तक के पहले खंड के लिए कर की दर 30 प्रतिशत के बजाए 25 प्रतिशत होगी। लेकिन 20,001 रुपए से 25,000 रुपए तक के खंड पर कर की वर्तमान दर 30 प्रतिशत ही रहेगी। 25,001 रुपए से 30,000 रुपए तक के अगले खंड के लिए कर की दर 1 प्रतिशत ब्रॉक बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी जाएगी। अधिभार की दर में वृद्धि होने के बाद भी निचले आय-खंडों में आने वाले व्यक्ति और कतिपय श्रेणियों के हिन्दू अभिभक्त कुटुम्ब इस समय जितना कर देते हैं उससे कम कर देंगे। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप राजस्व में पूरे एक वर्ष में 35 करोड़ रुपए और 1983-84 में 28 करोड़ रुपए की हानि होगी।

76. बचतों को प्रोत्साहन देने के उपाय के रूप में, मैं जीवन बीमा, भविष्य निधियों, आदि जैसे विनिर्दिष्ट प्रकार की बचतों के संबंध में कुल सकल आय की 30 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ, लेकिन धन राशि के रूप में व्यक्त उच्चतम सीमा लागू रहेगी। इसके अलावा, मेरा इरादा बचत के उपलब्ध माध्यमों में राष्ट्रीय बचत-पत्रों के छठे और सातवें निर्गम को शामिल करके, इन माध्यमों का विस्तार करने का है। इससे विशेष रूप से उन लोगों को लाभ पहुंचेगा, जो अश्रेष्ठ अवस्था में हैं और अपने कार्य-शील जीवन के अन्तिम भाग में हैं तथा जो जीवन-बीमा और अन्य सविदात्मक प्रकार की बचतों का लाभ उठाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। इस उपाय से पूरे एक वर्ष में राजस्व में 15 करोड़ रुपए की और अगले वर्ष 12 करोड़ रुपए की हानि होने की संभावना है।

77. इस समय विनिर्दिष्ट दीर्घाधिक निवेशों से होने वाली आय में से 4000 रुपए तक की राशि को छूट मिली हुई है और इसके अलावा एक वर्ष में अधिक की अधि के लिए बैंक में जमा राशियों और प्रतिभूतियों से मिलने वाले व्याज की 2000 रुपए तक की राशि को भी छूट प्राप्त है। सरलीकरण के उपाय के रूप में, मैं इन अलग-अलग छूट-सीमाओं को आपस में मिलाने और इसे 6000 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों से होने वाली आय के संबंध में 3000 रुपए की मौजूदा पृथक छूट अपरिचित बनी रहेगी। इन प्रस्तावों

के फलस्वरूप, विनिर्दिष्ट निवेशों से होने वाली ऐसी कुल आय, जिसे कर में छूट प्राप्त है, 9000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी। इससे बचतों को और प्रोत्साहन मिलेगा।

78. सम्मानित सदस्य महसूस करेंगे कि अधिभार में वृद्धि होने के बावजूद, उक्त प्रस्तावों का प्रभाव कुल मिलाकर ऐसा होगा, जिससे कम कर देने वाले निर्धारितियों (असेसी) की कर-संबन्धी देनदारियों में वृद्धि नहीं होगी। जहाँ तक शेष लोगों का संबंध है, चूंकि मेरा आशय बचतों पर नहीं बल्कि मुख्यतः उपभोग पर अधिभार लगाने का है, इसलिए मैंने अधिभार को विनिर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों में की जाने वाली वैयक्तिक बचतों को बढ़ावा देने के उपायों के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है।

79. मैं अनिवार्य जमा योजना (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 को और दो वर्षों की अवधि के लिए लागू रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय, 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को धनराशि जमा कराने से छूट प्राप्त है। मैं इस आयु-सीमा को 70 वर्ष से घटा कर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूँ। जो व्यक्ति पहली अप्रैल, 1983 को 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे उन्हें, अपनी इच्छानुसार अपनी जमा राशियाँ पहली जून, 1983 को अथवा उसके बाद निकालने का अधिकार होगा।

80. इस समय उन मामलों में जहाँ किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाली निवल राशि का निवेश 7-वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में कर दिया जाता है, पूंजी अभिलाभों पर कोई कर नहीं लगता। मुझे बताया गया है कि यह परिपक्वता अवधि कुछ लम्बी है। निवेश के अन्य विकल्पों की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि साधनों का प्रवाह घाटित दिशाओं में हो, निवल प्रतिफल (नेट कन्सिडरेशन) का निवेश केन्द्रीय सरकार के 3 वर्षों की परिपक्वता वाले नए बांडों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की विशेष श्रृंखला और आवास तथा नगर विकास निगम के ऐसे ऋणपत्रों में, जिनकी परिपक्वता अधि उन पर दिए जाने वाले ब्याज के अनुसार उपयुक्त रूप से समायोजित की गई हो, किए जाने पर भी मैं यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

81. जैसाकि मैंने पहले बताया है, मैंने भारत में पूंजी-निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों को दिए जाने वाले कर-प्रोत्साहनों को और उदार बनाने का निश्चय किया है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा की प्रेषणाओं द्वारा भारत में किए गए विनिर्दिष्ट निवेशों से उन्हें होने वाली आय पर मैं 20 प्रतिशत की समान दर (प्लैट रेट) पर कर और इसके अलावा अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इन निवेशों में भारतीय कंपनियों के शेयर और ऋण-पत्र (डिबेंचर) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट और सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों के अन्तरण से होने वाले दीर्घाधिक पूंजी अभिलाभों पर भी प्रस्तावित समान दर से का

नगरीय। ऐसी आमदनियों को उनकी अन्य भारतीय आम-दनियों की संगणना करने समय भी हिमाव में नहीं लिया जाएगा। यदि उनकी भारत में कोई अन्य आय नहीं होगी और उनकी आय से प्रस्तावित समान दर पर कर की कटौती कर ली गई होगी, तो उन्हें कर-विवरणियां प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा। इन अनिवारियों को यह भी विकल्प होगा कि यदि वे चाहेंगे तो वे निवासी करदाताओं पर लागू सामान्य दरों पर भी करभ्रदा कर सकेंगे। ऐसे पूँजी-निवेशों को धन-कर से भी छूट प्राप्त होगी विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारत में अपने संबन्धियों को उपहार में दी गई ऐसी परि-मपत्तियों को दान-कर से छूट प्राप्त होगी।

82. अब मैं अपने निगम-कर सम्बन्धी प्रस्तावों को लूंगा। अपने भाषण में इससे पहले मैंने कम्पनियों द्वारा अधिक आन्तरिक साधन जुटा कर और प्रदर्शनात्मक उपभोग पर रोक लगा कर निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। मेरा विश्वास है कि सरकार और कम्पनियां दोनों इस उद्देश्य की पूर्ति में योगदान दे सकती हैं।

83. मुझे कई समितियों और उद्योगों के प्रतिनिधि संगठनों द्वारा बताया गया है कि प्रतिस्थापन और आधुनिकी-करण की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए निगम क्षेत्र के पास जो आन्तरिक साधन उपलब्ध हैं, वे अपर्याप्त हैं। मुझे इस तर्क में सार दिखाई देता है। तदनुसार, मैं संयंत्र और मशीनों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास की सामान्य दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ मैं संयंत्र और मशीनों की छोटी मर्दों के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत बट्टे खाने में यावी जाने वाली राशि की मौद्रिक सीमा को भी 750 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर रहा हूँ। संयंत्र और मशीनों में किए जाने वाले पूँजी निवेश को जो अन्य सम्बन्धित लाभ इस समय मिलते हैं, वे मिलते रहेंगे। मूल्यह्रास से सम्बन्धित उपबन्धों को उदार बनाए जाने से राजस्व में एक पूरे वर्ष में 140 करोड़ रुपए और वर्ष 1983-84 में 112 करोड़ रुपए की हानि होगी।

84. सम्मानित सदस्यों का याद होगा कि गत वर्ष मैंने ऊर्जा की वचत करने और पर्यावरण के प्रदूषण को न्यून-तम करने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले यंत्रों और प्रणालियों पर उनकी लागत के 30 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास देने का प्रस्ताव किया था। मैं इसे भी आगे जाकर और ऊर्जा की वचत करने वाले यंत्रों और प्रणालियों पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। जहाँ तक पर्यावरण के प्रदूषण को न्यूनतम करने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले यंत्रों और प्रणालियों का सम्बन्ध है, मैं निवेश-मॉक (इनवेस्-मेंट अलाउंस) को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

85. उद्योगों का शहरी इलाकों से हटकर दूररे स्थानों पर चले जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और

जन संकुलित नगरों में भीड़-भाड़ को घटाने और प्रदूषण को कम करने के उपाय के रूप में, कारबार के प्रयोजन से इस्तेमाल की जा रही इमारतों अथवा भूमि के अन्तरण से प्राप्त पूँजी ऑनलाइन को कर में छूट मिलती है, यदि उसका उपयोग नए स्थान पर कारबार के प्रयोजन से भूमि प्राप्त करने अथवा इमारतों का निर्माण करने के लिए किया जाए। मैं कर की इस छूट को मशीनों और संयंत्रों के अन्तरण से होने वाले पूँजी ऑनलाइन पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

86. मैंने इससे पहले व्याज दरों के ढाँचे में कमी करने का उल्लेख किया था। बैंकों द्वारा दी जा रही राहत में अपने योगदान के रूप में और उत्पादन पर पूँजीनिवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं व्याज कर अधिनियम के अन्तर्ग लागू कर की दर को मौजूदा दर से आधा करने का प्रस्ताव करता हूँ। 31 मार्च, 1983 के बाद उद्भूत उस व्याज के सम्बन्ध में, जिस पर कर लग सकता है, व्याज कर की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 3-1/2 प्रतिशत कर दी जाएगी। इस उपाय के कारण होने वाली 130 करोड़ रुपए की हानि के लगभग आधे भाग की पूर्ति, व्यापार और उद्योगों की उधार सम्बन्धी कटौती-योग्य लागत के कम हो जाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर-राजस्व प्राप्त होने से हो जाएगी।

87. निगम कर ढाँचे के सम्बन्ध में मेरा एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना है। इसलिए, मैं पिछले वर्ष घोषित दो योजनाओं को जारी रख रहा हूँ और उन्हें अधिक उधार बना रहा हूँ।

88. जहाँ तक अतिरिक्त उत्पादन सम्बन्धी योजना का सम्बन्ध है, मैं उसका ब्याग बाद में अप्रत्यक्ष करों वारे में अपने प्रस्तावों की चर्चा करने के समय दूंगा।

89. जहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है, मेरे द्वारा पिछले वर्ष घोषित की गई योजना में उन निर्यातकों को कुछ कर राहत दी गई थी, जिनका किसी वर्ष का कुल निर्यात उससे ठीक पहले के वर्ष के निर्यात से 10 प्रतिशत से भी अधिक का हुआ हो। पिछले वर्ष की योजना के अन्तर्गत जो कुल राहत दी जा सकती है, वह अधिक से अधिक देय कर के 10 प्रतिशत तक सीमित थी। मैं अब इस योजना को सरल और उदार बनाने और न्यूनतम अर्हक राशि तथा राहत की सीमा सम्बन्धी दोनों शर्तों को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ। निर्यातकों के कारबार में जो वृद्धि हुई हो, उसके 5 प्रतिशत के बराबर की राशि को, वे अपनी कर-योग्य आय की संगणना करने समय, घटा सकते हैं। इस प्रकार, नई योजना के अन्तर्गत, निर्यात कारबार में हुई समूची वृद्धि पर राहत प्राप्त हो सकेगी। कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं को

छोड़कर, सभी वस्तुओं के निर्यात पर यह रियायत मिल सकेगी। चूंकि यह नया उपबन्ध 1983-84 के निर्धारण वर्ष से लागू होगा, इसलिए पिछले वर्ष किए गए उपबन्ध को हटाने का प्रस्ताव है।

90. सम्मानित सदस्यों को इस तथ्य की जानकारी अवश्य होगी कि कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो फलफूल तो रही हैं लेकिन कोई कर अदा नहीं कर रही हैं अथवा नाम मात्र का ही कर देती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये कम्पनियां आयकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उपलब्ध कर-प्रोत्साहनों और रियायतों का लाभ उठा रही हैं। मेरे लिए यह एक चिन्ता का विषय है कि हमारी कर प्रणाली के अंतर्गत बहुत-सी ऐसी कम्पनियां, जो भारी मुनाफा कमाती हैं, अपनी करसंबंधी देनदारी को शून्य तक घटा लेती हैं, हालांकि वे ऊंचे लाभांश देती आ रही हैं। यह उचित प्रतीत होता है कि मुनाफा कमाने वाली और समृद्ध कम्पनियां एक ऐसे समय में जो समाज के अन्य और कम खुशहाल वर्ग का अंशदान राष्ट्रीय राजकोष में करें। इसलिए मैं यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं कि राजकोषीय प्रोत्साहन और रियायतें मुनाफे के 70 प्रतिशत से अधिक भाग पर लागू नहीं होंगी। इसका अर्थ यह होगा कि कम्पनियां अपने मुनाफों के कम से कम 30 प्रतिशत भाग पर न्यूनतम कर अदा करें।

91. स्वदेशी कम्पनियों के मामले में, कम्पनियों की कुल आय के आधार पर, कर की विवेकी दरों को हटाने का प्रस्ताव है।

92. सरकारी ऋण के उपाय के रूप में, मैं विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों पर इन कम्पनियों को प्राप्त व्याज की सकल राशि पर 25 प्रतिशत की समान दर से आय-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

93. कम्पनियों द्वारा देय आय-कर पर इस समय ऐसे आय-कर के 25 प्रतिशत की दर से अधिभार (सरचार्ज) लगता है। मैं अधिभार की दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। किन्तु, कम्पनियों द्वारा देय आय-कर अधिभार के बदले कम्पनियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली एक योजना के अंतर्गत, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास धनराशि जमा करा सकेंगे। मैं इस उपाय से प्राप्त हो सकने वाले राजस्व की किसी राशि को हिसाब में नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कम्पनियां अतिरिक्त अधिभार की राशि को वस्तुतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा करा देंगी। इस प्रकार जमा कराई गई राशियों से आधुनिकीकरण के लिए धनराशियां उपलब्ध हो सकेंगी और इस प्रकार वे वापस निगम क्षेत्र में ही चली जायेंगी।

94. हमारे निगम-करों का ढांचा भिन्न-भिन्न प्रकार की बहुत-सी कटौतियों से अभिभूत है। हालांकि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रत्येक कटौती का कोई-न-कोई फायदा है; लेकिन कुल मिलाकर इसके परिणामस्वरूप कर प्रशासन जटिल हो जाता है, दुरुपयोग के लिए मौका मिलता है और राजस्व की वृद्धि कम हो जाती है। इस ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से मैंने विभिन्न कटौतियों की समीक्षा की है।

95. इस समय आय-कर अधिनियम में ऐसी कम्पनी या सहकारी समिति (सोसाइटी) द्वारा किए गए व्ययों की भारत कटौती के लिए व्यवस्था है जो कृषि, पशुपालन, मृगीपालन या डेरी उद्योग के उत्पादों का कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल करती है। जिन व्ययों के संबंध में भारत कटौती की अनुमति है, वे सीधे निर्धारित (असेसी) के कारबार में संबंधित नहीं होते। मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी कम्पनियां या सहकारी समितियां आगे से केवल व्ययों की कटौती के लिए ही हकदार होंगी, भारत कटौती के लिए नहीं।

96. आय-कर अधिनियम में ऐसे व्ययों या अंशदानों के लिए कटौती की व्यवस्था है जो निर्धारितियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए किए गए हों। विभिन्न सहकारी द्वारा अनुमोदित, चल रहे कार्यक्रमों को कटौती के ये लाभ, समयबद्ध कार्यक्रमों के मामले में समाप्ति की तारीख तक और अन्य मामलों में 29 फरवरी, 1984 मिलते रहेंगे। लेकिन, दुरुपयोग की संभावना को रोकने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस संबंध में और कोई कटौतियां करने की अनुमति नहीं दी जाए। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ग्रामीण विकास के असली कार्यक्रमों को निगम सहायता से वंचित कर दिया जाए। सरकार शीघ्र ही 'ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री का कोष' नाटक एक कोष स्थापित करेगी जिसमें किए जाने वाले अंशदान आय-कर अधिनियम के अंतर्गत कर-मुक्त होंगे।

97. पशु-प्रजनन या डेरी उद्योग अथवा मृगीपालन के कारबार से और कुकुरमुत्ता (खेबू) उगाने के कारबार से प्राप्त होने वाले लाभों और अभिलाभों के संबंध में जो अब तक विशेष कटौती अनुमत थी, उसे वापस लेने का प्रस्ताव है। ऐसे काम-धंधों के लिए दी जाने वाली राजकोषीय रियायत को जारी रखने का मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की गुंजाइश है। किन्तु, तेलहनों, पत्तों और सब्जियों की प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें मजबूत करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी सहकारी समितियों को कर से पूरी छूट दी जाए जैसे कि डेरी संबंधी सहकारी समितियों के मामले में दी जाती है।

98. प्रौद्योगिकी के समस्तरीय (हारिजेंटल) अन्तरण के संबंध में कर संबंधी रियायत 1969 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशी प्रौद्योगिकी के बार-बार आयात को निरुत्साहित करता था। मैं देखता हूँ कि इस रियायत का कर-परिवर्जन के लिए दुरुपयोग किया जाने लगा है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निर्धारण वर्ष 1984-85 से इस रियायत को वापस ले लिया जाए।

99. सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि व्यापार और उद्योग द्वारा खास तौर से यन्त्रा, विज्ञापन और ऐमी रा अन्य मरी पर अत्यधिक और निरर्थक व्यय किया जाता है। सादनों का वातावरण पैदा करने और व्यापार तथा उद्योग द्वारा किए जाने वाले अनुवादक, परिहृत्य और प्रदर्शनात्मक खर्च को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि कर-योग्य लाभों की संगणना करते हुए ऐसे व्यय के 20 प्रतिशत भाग को नामंजूर कर दिया जाएगा। अधिकतर अधिनियम में एक निश्चित सीमा से परे सत्कार व्ययों की नामंजूरी और अतिथिगृहों के अनु-रक्षण पर हुए सम्पूर्ण व्ययों की नामंजूरी की व्यवस्था है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 'सत्कार व्यय' और 'अतिथि गृह' शब्दों को परिभाषित कर दिया जाए ताकि इन शब्दों के सही तात्पर्य के बारे में कोई संदेह न रहे। इन उपायों से एक पूरे वर्ष में 50 करोड़ रुपए और 1983-84 में 40 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इन उपायों और मूल्यहास मोक (डिप्रीशिएशन अलाउन्स) में वृद्धि करने का असर यह होगा कि अनुत्पादक व्यय के मुकाबले पूंजी-निवेश के प्रति, कराधान के मामले में, बहुत ही अधिमान्यतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा।

100. ऐसे कई मामले देखने में आए हैं जिनमें करदाता लंबे समय तक उत्पाद-शुल्क, भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि के संबंध में अपनी कानूनी देनदारी पूरी नहीं करते। फिर भी अपने आय-कर के निर्धारण के प्रयोजन से इस देनदारी की राशि की कटौती किए जाने की मांग करते हैं जबकि वे खुद कानूनी कार्यवाई का महारा लेते हैं और इस प्रकार वे सरकार को तो उसकी वाजिब कर-राशि से वंचित करते हैं और खुद अदायगी न करने का फायदा उठाते हैं। ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि करदाता चाहे किसी भी लेखा-पद्धति का अनु-सरण करे, कर-योग्य लाभों की संगणना में कानूनी देनदारी के लिए कटौती की अनुमति उसी वर्ष में और उसी सीमा तक दी जाएगी, जिस वर्ष और जहां तक वह वास्तव में अदा कर दी गई होगी। इसके फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में 100 करोड़ रुपये और 1983-84 में 80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

101. यह देखने में आया है कि कुछ लोग अल्पजन-धारित कंपनियां बनाकर और उनको अपने धन की कई मदों

खासतौर से आभूषण, बुलियन और जमीन-जायदाद का अंतरण करके वैयक्तिक धन-कर की देनदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन कंपनियों पर धन-कर नहीं लगना और ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में भी कंपनी की परिसम्पत्तियों के वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता, इसलिए जो लोग अल्पजन-धारित कंपनियों में ऐसी अनुत्पादक परिसम्पत्तियां धारण करते हैं, वे काफी हद तक अपनी धन-कर संबंधी देनदारी को सफलतापूर्वक कम कर लेते हैं। ऐसे लोगों द्वारा किए जाने वाले कर-परिवर्जन को रोकने के उद्देश्य से, मैं अल्पजन-धारित कंपनियों के मामले में, एक सीमित रूप से, धन-कर पुनः लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसलिए, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूँ कि अल्पजन-धारित कंपनियों के मामले में, विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों, जमे कि उनके आभूषण, मोता, बुलियन, इमारतों और जमीनों के मूल्य के रूप में व्यक्त निवल धन पर 2 प्रतिशत की दर से धन-कर लगा दिया जाए। कंपनी द्वारा अपने कारखाने के प्रयोजनों के लिए फक्टरी, गोदाम, भांडागार, होटल या कार्यालय के रूप में इस्तेमाल में लाई जाने वाली इमारतों अथवा अपने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के आवास के लिए काम में लाए जाने वाले भवनों का निवल धन में शामिल नहीं किया जाएगा।

102. सम्मानित सदस्य महसूस करेंगे कि निगम क्षेत्र के संबंध में मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य, संक्षेप में, यह सुनिश्चित करना है कि मुनाफा कमाने वाली प्रत्येक कंपनी उस वर्ष कुछ कर अवश्य दे जिस वर्ष उसे मुनाफा हुआ हो, कर से बच निकलने के रास्ते बंद कर दिए जाएं और कटौतियों की संख्या कम कर दी जाए, आधुनिकीकरण और पुनः निवेश के लिए अधिक धनराशियां उपलब्ध हों, कम व्याज प्रभारों के जरिए लागत कम की जाए और प्रदर्शनात्मक व्ययों में कमी हो, और खासतौर से निर्यात के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन को सम्यक् प्रोत्साहन मिले।

103. बहुत से पूर्त और धार्मिक न्यास (ट्रस्ट) और संस्थाएं, निस्संदेह, प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। दुर्भाग्यवश यह भी सही है कि उनमें से बहुतों का इस्तेमाल कर-परिवर्जन तथा धन संग्रह के माध्यम के रूप में श्रीर संरक्षण प्रदान करने के साधन के रूप में किया जा रहा है, और मैं एक उदासीन दृष्टिकोण बनकर नहीं रह सकता। यही समय है जबकि इन मामलों को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं।

कराधान विधिया (संशोधन) अधिनियम, 1975 में न्यास निधियों के निवेश के लिए एक पद्धति निर्धारित की गई थी, और यह उपबंध था कि जो न्यास 31 मार्च, 1978 के बाद शुरू होने वाले लेखा वर्षों से इस निवेश पद्धति का पालन नहीं करेंगे वे कर छूट पाने के हकदार नहीं होंगे। किन्तु, तत्संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह परिवर्तन अधिक सुव्यवस्थित रूप से हो, 1977 में इस तारीख को तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। चूंकि पूर्त और धार्मिक न्यासों से संबंधित उपबंधों का सारा मामला

आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के विचाराधीन था, इसलिए निवेश की नई पद्धति के प्रवर्तन की तारीख को गत वर्ष फिर एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया।

अब मैंने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है। मुझे इस बात में कोई श्रौचित्य दिखाई नहीं देता कि न्यास निधियों को व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के शेयर भी शामिल हैं, निवेश करने की अनुमति दी जाए। इसलिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि सभी न्यास निधियों का विनिर्दिष्ट रूपों, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, अनुसूचित बैंकों की जमा राशियों, अनुमोदित वित्तीय निगमों आदि में निवेश किया जाए। लेकिन स्थावर सम्पत्तियों में निवेश करने की अनुमति आगे भी जारी रहेगी। मैं सभी पूर्त और धार्मिक न्यासों को इस बात के लिए नोटिस दे रहा हूँ कि वे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शेयरों और अन्य निवेशों में लगाई गई अपनी धन-राशियों को 30 नवम्बर, 1983 तक वापस निकाल लें। किन्तु, न्यासों की कम्पनियों के उन शेयरों को, जो 1 जून, 1973 को उनकी मूल निधि का अंग थे, और उस तारीख तक प्राप्त बोनस शेयरों को रखने की अनुमति दी जाएगी। कुछ न्यास वाणिज्यिक पद्धतियों पर कारबार चलाते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं। कोई कारण नहीं कि कारबार की ऐसी आय पर कर न लगाया जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ सभी पूर्त और धार्मिक न्यासों, जिनमें वे न्यास भी शामिल हैं जो अब तक अधिसूचना के द्वारा कर-मुक्त थे, कारबार की आय पर निर्धारण वर्ष 1984-85 से कर लगने लगेगा। कारबार से आय प्राप्त करने वाले न्यासों को नई निवेश-पद्धति का भी पालन करना होगा, यदि वे अपनी अन्य आय के बारे में कर से छूट लेना चाहेंगे।

104. सम्मानित सदस्यों को निस्संदेह ज्ञात है कि कृषि भूमि के संबंध में संपदाशुल्क एक राज्य विषय है और केन्द्र ने कृषि भूमि पर संपदा-शुल्क केवल उन्हीं संकल्पों के आधार पर लगाया है जो राज्यों ने इस संबंध में संघ को ऐसा करने की समर्थता प्रदान करने के लिए पारित किए हैं। हमारा अनुभव है कि कृषि भूमि के मूल्यनिर्धारण के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। इस शुल्क के लगने से पिछले कुछ वर्षों में कोई खास प्राप्ति भी नहीं हुई है। इसके अलावा, कृषि भूमि, जिसमें बागान भी शामिल है, पर धन-कर समाप्त कर दिए जाने के बाद, कृषि भूमि पर संपदा-शुल्क को लागू रखने के लिए कोई व्यावहारिक औचित्य दिखाई नहीं देता। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि भूमि पर लगने वाले संपदा-शुल्क को हटा दिया जाए। चूंकि संपदा-शुल्क अधिनियम को राज्यों के विधान-मंडलों के आवश्यक संकल्पों के बाद ही संशोधित किया जा सकता है, इसलिए इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

105. ब्याज-कर में कमी किए जाने से अगले वर्ष राजस्व में 104 करोड़ रुपए की हानि होगी। इस हानि के

एक भाग की पूर्ति हो जाने का अनुमान है; इसे हिसाब में लेने पर, निगम-कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से अगले वर्ष 104 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। आय-कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से अगले वर्ष केन्द्र को 25.6 करोड़ रुपए का निवल राजस्व प्राप्त होगा और राज्यों को 28 करोड़ रुपए की हानि होगी।

106. अब मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की ओर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन को विदित ही है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे भुगतान-शेष पर बराबर दबाव पड़ रहा है। इसके बावजूद, हमने आयातों की एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया है, जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं जैसी आयात की जाने वाली निविष्टियों (इनपुट) पर्याप्त मात्रा में मुलभ हो सकें। साथ ही मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि विदेशों के ऐसे निर्यातक, जिन्हें इस समय बाजार की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी नीतियों से लाभ उठाकर भारत के बाजार में अनुचित रूप से सस्ता माल बेचें जिससे भारत के उद्योग को हानि हो। मेरा विश्वास है कि हमें सीमा-शुल्कों के साधन का उपयोग न केवल राजस्व संग्रह के लिए बल्कि अपने भुगतान-शेष और औद्योगिक विस्तार को समर्थन प्रदान करने के लिए भी करना चाहिए। अपने कर-प्रस्तावों को तैयार करते समय मैंने कर परिवर्जन और अपवंचन को कम से कम करने का भी प्रयास किया है और मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इन प्रस्तावों से मुद्रास्फीति को बढ़ावा न मिले।

107. पहले मैं सीमा-शुल्कों को लेता हूँ। मेरा मुख्य प्रस्ताव यह है कि उन सहायक सीमा-शुल्कों को जारी रखा जाए जो पहली बार 1973 में लगाए गए थे और उसके बाद जो हर साल फिर से लगा दिए जाते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्तमान प्रभावी दरों में कुछ अपवादों के साथ 5 प्रतिशतांशों की वृद्धि कर दी जाए। सहायक शुल्क की कानूनी दर को 50 प्रतिशत पर और अधिकतम प्रभावी दर को केवल 35 प्रतिशत पर लागू रखने का प्रस्ताव है। 15 प्रतिशत के इस अन्तर से हमें शुल्क के स्तर को उतना बढ़ाने में सहायता मिलेगी जो स्वदेशी उत्पादन को समर्थन प्रदान करने जैसे कारणों से जरूरी हो जाए। अख्त्यारी कागज और कच्चे पेट्रोलियम पर सहायक सीमा-शुल्क नहीं बढ़ाया जायेगा। साथ ही, उर्वरकों, मिट्टी के तेल, तेज गति वाले डीजल तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं को सहायक शुल्कों से जो इस समय पूरी छूट मिली हुई है उसे जारी रखा जाएगा। इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 254.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

108. मेरे अगले प्रस्ताव का सम्बन्ध रसायनों से है। वस्तुओं के इस समूह पर सामान्यतः 60 प्रतिशत मूल्यानुसार की बुनियादी दर से सीमा-शुल्क लगता है। मेरा विश्वास है कि रसायनों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट आ जाने से टैरिफ दर को बढ़ाकर शत प्रतिशत मूल्यानुसार करना और सामान्य प्रभावी दर को बढ़ाकर 70 प्रतिशत

मूल्यानुसार कर देना उचित होगा। रसायनों के कतिपय समूहों पर 40 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की जो टैरिफ दरें लागू हैं उन्हें भी इसी प्रकार बढ़ाया जा रहा है। औषधीय रसायनों और औषधियों, कीटनाशी दवाओं इन्सैक्टिसाइड नाशकमार दवाओं (पैस्टिसाइड), कवकनाशी (फंगीसाइड) रसायनों, उर्वरकों, चमड़ा कमाने के रसायनों आदि को प्रायः प्रस्तावित वृद्धि के दायरे में बाहर रखा गया है। इस उपाय से पूरे एक वर्ष में 37.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

109. मेरा यह भी प्रस्ताव है कि जस्ता धातु पर सगे प्रभावी बुनियादी आयात-शुल्क को 45 प्रतिशत में बढ़ाकर 55 प्रतिशत मूल्यानुसार और सीमा धातु के आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। इस समय सीसे की रही और उसकी छीजन (स्ट्रैप) पर प्रतिस्नुतुलनकारी शुल्क की जो आंशिक छूट दी जा रही है उसे भी मैं वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। इन उपायों से पूरे एक वर्ष में 12.8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और हमसे स्वदेशी उत्पादकों की वित्तीय सक्षमता बढ़ेगी।

110. हमारे इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लाभ के लिए, 45 प्रतिशत मूल्यानुसार की वर्तमान रियायती बुनियादी आयात-शुल्क दर को कच्चे माल और संघटकों की चार और मदों पर लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत मूल्यानुसार की वर्तमान रियायती बुनियादी आयात-शुल्क दर को 14 और मदों पर लागू करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से एक वित्तीय वर्ष में राजकोष को 1.22 करोड़ रुपए की हानि होगी।

111. एक और रियायत है जिसका सम्बन्ध विदेशों से डाक द्वारा या हवाई-जहाज द्वारा प्राप्त होने वाले वास्तविक उपहारों में है। ऐसे उपहारों के लिए मौजूदा शुल्क-मुक्त सीमाएं 1968 में निर्धारित की गई थीं। विदेशों से डाक द्वारा या हवाई जहाज द्वारा आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों और औषधियों के वास्तविक उपहारों तथा डाक द्वारा आयात की जाने वाली अन्य वस्तुओं की शुल्क-मुक्त सीमा को बढ़ा कर 200 रुपए कर देने का प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि इस सीमा को उदार बना दिए जाने का वे लोग निश्चय ही स्वागत करेंगे जिन्हें विदेशों से अपने मित्रों और सम्बन्धियों से वास्तविक उपहार प्राप्त होते रहते हैं। इस उपाय से पूरे एक वर्ष में 3.71 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

112. मैं विदेशों से भारत लौटने वाले यात्रियों द्वारा लाए जाने वाले अमवाब की वस्तुओं पर आयात-शुल्कों से सम्बद्ध उपबंधों की युक्तिमंगत और उदार बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। असबाब की वर्तमान 1000 रुपए की शुल्क-मुक्त सीमा 1978 में निर्धारित की गई थी। मैं वयस्कों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 1250 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूँ। अवयस्कों तथा अन्य श्रेणियों के यात्रियों

के लिए भी तदनु रूप वृद्धि कर दी जाएगी। विदेशों में काम करने वाले उन भारतीय श्रमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जो वहां प्रायः एक वर्ष के ठेके पर जाते हैं और फिर भारत वापस आते हैं, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस्तेमाल की गई घरेलू वस्तुओं के लिए, कुछ अपवादों सहित, शुल्क-मुक्त सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया जाए। पहले शुल्क-योग्य मूल्य-खण्ड पर बुनियादी शुल्क की दर 130 प्रतिशत बनी रहेगी, जबकि पहले शुल्क-योग्य मूल्य-खण्ड के अलावा मूल्य पर, कुछ वस्तुओं को छोड़कर, शुल्क की दर 300 प्रतिशत से घटाकर 200 प्रतिशत मूल्यानुसार की जा रही है। सहायक शुल्क इसके अलावा होगा। असबाब की उन वस्तुओं की सूची को भी छोटा किया जा रहा है जिन्हें बिना शुल्क दिए देश में लाने की अनुमति नहीं दी जाती। मुझे विश्वास है कि इन उपायों से देश में आने वाले यात्रियों की सीमा-शुल्क संबंधी निकामी की जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे कम हो जाएंगी। मेरे विचार में इन रियायतों के कारण राजस्व में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

113. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में भी कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि क्षेत्र में इस विभाग के कार्यचालन को दोषरहित बनाया जा सके और राजस्व संग्रह के कार्य को और अधिक कुशल बनाया जा सके। इन परिश्रमों का सम्बन्ध मुख्य रूप से अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो खोलने और भांडागारण तथा शुल्क-वापसी के उपबंधों से है। सीमा-शुल्क राजस्व की एक काफी बड़ी राशि माल के बहुत देर तक भांडागारों में पड़े रहने के कारण रुकी रहती है और इसलिए उपभोग्य वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के मामले में भांडागारण की समय-सीमा को घटाकर एक वर्ष और अन्य वस्तुओं के मामले में इसे तीन महीने कर देने का प्रस्ताव है। शुल्क-वापसी की अदायगियों को जल्दी निपटाने के उपाय के रूप में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि शुल्क-वापसी का दाव करने के लिए इतना ही काफी है कि माल निर्यात के लिए भारत से बाहर के स्थान पर दाखिल हो गया है। जिस न्यूनतम राशि के लिए शुल्क-वापसी के दावे पर विचार किया जाएगा, उसे भी 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जा रहा है।

114. सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के लिए ऐसी शक्ति प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है जिससे सरकार टैरिफ में बताए गए आधार से भिन्न आधार पर शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित कर सके। अतः यदि शुल्क की टैरिफ दर मूल्यानुसार आधार पर लगाई गई है तो सरकार को शुल्क की प्रभावी दरें वजन, परिमाण आदि के आधार पर निर्धारित करने का अधिकार होगा।

115. महोदय, अब मैं उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों पर आता हूँ। मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य वहां से अप्रत्याशित लाभों की बटोरना है जहां मुझे विश्वास है,

बे होते हैं और अलग-अलग मर्दों पर अतिरिक्त शुल्कों के भार को अपेक्षाकृत कम अनुपात तक सीमित करना है। मैंने लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को भी सामने रखा है क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र देश के उद्यम-कर्ताओं के लिए एक पाठशाला है और इसमें आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को दूर करने में भी सहायता मिली है।

116. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेष उत्पाद-शुल्कों को मौजूदा दरों पर 1983-84 में जारी रखा जाए।

117. जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, बाजार में सीमेंट की कीमतें बहुत ऊंची चढ़ी हुई हैं। अनुचित लाभों को बटोरने के लिए मैं आम इस्तेमाल में आने वाली सीमेंट की किस्म पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क की दर को 135 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 205 रुपए प्रति मेट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। मिनी सीमेंट कारखानों में तैयार किए गए सीमेंट पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क की दर भी 100 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए हो जाएगी और इस प्रकार उत्पाद-शुल्क के मामले में मिनी सीमेंट कारखानों के लिए 35 रुपए प्रति मेट्रिक टन का मौजूदा अन्तर आगे भी बना रहेगा। एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से 182 करोड़ रुपए तथा सीमेंट के आयात पर लगे प्रतिशतनुलनकारी शुल्कों से 6 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

118. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत कई वस्तुएं आती हैं जो टैरिफ में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं होती। इन पर लगे उत्पाद-शुल्क की दर 1979 में बराबर 8 प्रतिशत मूल्यानुसार चली आ रही है। अब मैं इसे 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से पूरे एक वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से 120 करोड़ रुपए तथा प्रतिशतनुलनकारी शुल्कों के रूप में 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह वृद्धि मूलतः तैयार वस्तुओं पर लागू होगी क्योंकि इस टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाला कच्चा माल और विनिर्मित निविष्टियां वर्तमान की भांति आगे भी शुल्क प्रतिदेयता के लिए पात्र रहेंगी। मैंने, जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, लघु उद्योग क्षेत्र को बचाने का ध्यान रखा है।

119. मैंने मानव-निर्मित रेशों, ब्लेंडिड यार्न और कपड़े (फैब्रिक) के बारे में भी कुछ मिले जुले उपायों का प्रस्ताव किया है। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि मैंने पिछले वर्ष अपने बजट में पालिएस्टर के बांछनीय अनुपातों के साथ मिश्रित कपड़े (ब्लेंडों) के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्पाद-शुल्कों में कई परिवर्तन किए थे। इस क्षेत्र में एक और उपाय के रूप में, मैं अब पालि-एस्टर मिश्रित सूती कपड़ों को पालिएस्टर मिश्रित विस्कोस कपड़ों की तुलना में प्रतियोगितात्मक वरीयता देने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों पर, जिन में 40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम पालि-एस्टर हो, बुनियादी और अतिरिक्त शुल्क के भार को 15

प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 6.5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है। लेकिन ये रियायती दरें पालिएस्टर फिलामेंट यार्न का इस्तेमाल किए जाने की सुरत में लागू नहीं होंगी। 40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम पालिएस्टर मिश्रित सूती यार्न पर शुल्क का कुल भार भी 11.25 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम किया जा रहा है। इन परिवर्तनों से पूरे एक वर्ष में 19.40 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

120. विस्कोस स्टेपल रेशे पर प्रभावी शुल्क की दर को 4 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है। इसके अलावा, इस रेशे के बढ़ते हुए आयात को निरुत्साहित करने के लिए, मैं साधारण विस्कोस स्टेपल रेशे पर आयात-शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने तथा साथ ही विस्कोस स्टेपल रेशे की उन्नत किस्मों पर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन उपायों से 5.6 करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ होगा।

121. आयातित पालिएस्टर रेशे के मामले में इसकी जहाज उतरती लागत और घरेलू कीमतों के बीच के अन्तर को देखते हुए, पालिएस्टर स्टेपल रेशे पर शुल्क की प्रभावी दर में 9 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इससे पूरे एक वर्ष में 9 करोड़ की रुपए आय होगी।

122. पालिएस्टर फिलामेंट यार्न अपेक्षाकृत ऊंची कीमत के कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है और मैं वस्त्र बनाने के काम आने वाले फिलामेंट यार्न पर प्रभावी उत्पाद-शुल्क में 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस वृद्धि का ऊँचे प्रतिशतनुलनकारी शुल्क के रूप में आयातित फिलामेंट यार्न पर भी बराबर प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि 750 डेनियर और उससे अधिक के फिलामेंट यार्न पर लागू नहीं होगी जो उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक पूरे वर्ष में उत्पाद शुल्क के रूप में 22.5 करोड़ रुपए का और प्रतिशतनुलनकारी शुल्कों के रूप में 5.6 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

123. उपर्युक्त वृद्धि के अनुरूप, मैं टैक्सटाइल डेनियरों के नाइलोन फिलामेंट यार्न पर उसी अन्तर से प्रभावी शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के रूप में 15.5 करोड़ रुपए के और प्रति-शतनुलनकारी शुल्कों के रूप में 50 लाख रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

124. कर-परिवर्तन का मुकाबला करने के उपाय के रूप में मैं कुछ वस्तुओं पर लगे शुल्क की दर को मूल्यानुसार से बदलकर मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार या मात्रानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। कागज के मामले में, मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार दर को अपनाते हुए, मैं छपाई और लिखाई के काम आने वाले कागज तथा अन्य

अधिकांश किस्मों के कागज और गत्ते के लिए एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। क्रफ्ट पेपर के लिए प्रभावी बुनियादी शुल्क 10 प्रतिशत मूल्यानुसार सहित 1910 रुपये प्रति मेट्रिक टन तथा अधिकांश अन्य प्रकार के कागज और गत्ते पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार सहित 1430 रुपये प्रति मेट्रिक टन होगा। लेकिन महानिदेशक, पूर्ति और निपटान का या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले छपाई के सफेद कागज के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत मूल्यानुसार की वर्तमान रियायती बुनियादी दर लागू रहेगी।

125. मैंने कागज के छोटे कारखानों को उपलब्ध वर्तमान रियायतों की भी समीक्षा की है। इस क्षेत्र को दी गई रियायतों को कारखाने की संस्थापित क्षमता के साथ जोड़ने में कुछ व्यावहारिक समस्याएँ समने आती रही हैं। इसलिए, मैं किसी एक वित्तीय वर्ष में की जाने वाली निकासियों की मात्रा के आधार पर इस क्षेत्र को दी गई रियायतों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस संबंध में दी जाने वाली छूट की मात्रा में भी समुचित संशोधन किया जा रहा है जिससे कागज बनाने के छोटे कारखानों को अपने उत्पादन में काफी वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाले कागज बनाने के ऐसे कारखानों में उत्पादित कागज के लिए शुल्क की दरें 560 रुपये, 900 रुपये या 1120 रुपये प्रति मेट्रिक टन होंगी और ये इस बात पर निर्भर करेंगी कि कागज बनाने के इन कारखानों से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कागज या गत्ते की निकासियों की मात्रा क्रमशः 3000 मेट्रिक टन, 7500 मेट्रिक टन या 16,500 मेट्रिक टन से अधिक न रही हो।

126. वानित जल (एग्रेटिड वाटर) के मामले में वर्तमान मूल्यानुसार दरों के स्थान पर शुल्क की मात्रानुसार दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव है। 200 मि० लि० की मोडे की बोतल पर 5 पैसे और अन्य वानित जलों की बोतलों पर 30 पैसे की दर से प्रभावी बुनियादी शुल्क लगेगा। लघु निर्माताओं को दी जाने वाली रियायतें बराबर जारी रहेंगी।

127. मोटर कारों के संबंध में वर्तमान मूल्यानुसार दर को मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार दर में बदला जा रहा है। प्रभावी दरें इजन की क्षमता पर आधारित होंगी और पेट्रोल-चालित तथा डीजल चालित कारों के लिए अलग-अलग होंगी।

128. दोपहिया वाहनो और ट्रैक्टरों के टायरों तथा विनिर्दिष्ट आकार के ट्रेलर टायरों के मामले में 60 प्रतिशत की वर्तमान बुनियादी टेरिफ दर को घटा कर 25 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है जो शुल्क की वर्तमान प्रभारी दरों का मूल्य है।

129. सबन को याद होगा कि पिछले नवम्बर में सिगरेटों पर शुल्क की रियायती दरें वापस ले ली गई थीं और सिगरेटों पर कानूनी दरें लागू कर दी गई थीं। लेकिन निर्धारण योग्य मूल्य को आंकने के तरीके पर विवाद खड़े हो जाने के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व की बसूलियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अनिश्चितता को हमेशा

के लिए समाप्त कर देने के विचार से मैं सिगरेटों के संबंध में शुल्क की मात्रानुसार दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। शुल्क की ये दरें सिगरेटों के पैकेटों पर छपी खुदरा बिक्री कीमतों से जुड़ी होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सस्ते सिगरेटों की खपत ज्यादा है, मैंने खुदरा कीमतों के आधार पर शुल्क की क्रमबद्ध दरें निर्धारित करने का प्रयास किया है। अब जिस शुल्क का प्रस्ताव किया जा रहा है, उसके अनुसार निम्नतम खंड पर शुल्क की दर 35 रुपये प्रति एक हजार सिगरेट होगी। आशा है कि इस उपाय से सरकार को इस मद से प्रत्याशित राजस्व प्राप्त हो जाएगा।

130. इन परिवर्जन-निरोधक सभी उपायों से लगभग 50 करोड़ रुपये का बड़ा राजस्व प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जो अन्यथा परिवर्जित हो जाता।

131. कई पक्षों से ऐसे प्रबल अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए उत्पाद-शुल्क में रियायत की वर्तमान योजना से इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि के मार्ग में रुकावट आती है और इस योजना को उदार बनाया जाना चाहिए। मैंने इस मामले पर विचार किया है। इस समय वस्तुओं के 70 विनिर्दिष्ट समूहों पर जो सामान्य योजना लागू है, उसके अनुसार निर्माताओं को 7.5 लाख रुपये की पहली निकामी पर शुल्क से पूरी छूट पाने का अधिकार प्राप्त है और 7.5 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की निकामियों पर देय शुल्क के 75 प्रतिशत की रियायती दर लागू होती है। मैं 15 लाख रुपये की इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर कर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही मैं पूरी छूट की 7.5 लाख रुपये की सीमा को घटा कर 5 लाख रुपये कर देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन, 5 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की निकामियों पर देय सामान्य शुल्क के 75 प्रतिशत की रियायती दर लागू रहेगी।

132. दो वस्तु समूहों अर्थात् श्रंगार और प्रसाधन सामग्री तथा दूसरे प्रशीतन और वातातुकूलन के उपकरणों तथा मशीनरी और उनके हिस्सों पर ऊंची दरों से उत्पाद-शुल्क लगता है और इन्हें सामान्य योजना से निकाल दिया जाएगा। इन मदों के लिए छूट की एक वैकल्पिक योजना की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत 2.5 लाख रुपये की कुल निकामियों वाले लघु निर्माताओं को शुल्क की अदायगी से पूरी छूट दे दी जाएगी और जिन निर्माताओं का उत्पादन 15 लाख रुपये तक होगा, उन्हें अपनी कुल निकामी पर सामान्य से आधी दर पर शुल्क देना होगा।

133. जहां तक टेरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लघु निर्माताओं को उपलब्ध छूट का संबंध है, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि पूर्ववर्ती वर्ष की निकामी के मूल्य के रूप में पावता की 30 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया जाए। इस उपाय से लघु उद्योग क्षेत्र के एकक अपना उत्पादन बढ़ाते हुए छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शुल्क की दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत

कर दिए जाने से, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, नई रियायतों की राशि 3 लाख रुपये तक की जा सकती है जब कि अब तक यह 2.4 लाख रुपए ही है।

134. मैं प्रस्ताव करना हूँ कि इन दोनों योजनाओं के मामले में, पात्रता का निर्धारण करने और शुल्क से छूट का लाभ उठाने के प्रयोजन से निकासियों के मूल्य की संगणना में, लघु उद्योगों को उपलब्ध छूटों के अन्तर्गत छूट-प्राप्त वस्तुओं से भिन्न अन्य छूट प्राप्त वस्तुओं की निकासियों को शामिल न किया जाए। लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई इन रियायतों के परिणामस्वरूप एक पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

135. 1982 के बजट के एक भाग के रूप में, मैंने कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तु समूहों के संबंध में, अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एक उत्पाद-शुल्क राहत योजना घोषित की थी। मैं इस योजना को जारी रखने का ही नहीं बल्कि अतिरिक्त निकासी के लिए शुल्क में राहत बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मौजूदा योजना में अतिरिक्त निकासियों के लिए कतिपय शुल्क दर समूहों के अंतर्गत आने वाली मदों के लिए शुल्क के 20 प्रतिशत की राहत और अन्य ऐसे समूहों के अंतर्गत आने वाली मदों के लिए शुल्क के 10 प्रतिशत की राहत की व्यवस्था है। मैं वर्तमान एक खंड की बजाए दो खंडों में प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि अतिरिक्त निकासी के प्रथम खंड के लिए इस समय दिए जा रहे 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के प्रोत्साहन को बढ़ाकर क्रमशः 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कर दिया जाए और उसके बाद वाले खंड के लिए बढ़ाकर 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर दिया जाए। मुझे आशा है कि उद्योग इस योजना का लाभ उठाएगा और उत्पादन बढ़ाएगा।

136. मैंने कुछ ऐसे परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है जिनसे राज्य सरकारें लाभान्वित होंगी। पहला परिवर्तन सूती और मानव निर्मित दोनों प्रकार के कोटेड फेब्रिक और फ्लोबड फेब्रिक के संबंध में है जहाँ आधार फेब्रिक पर लगने वाले शुल्क के अलावा, मूलानुसार 5 प्रतिशत का अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (बिक्री-कर के एवज में) लगाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 3.4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। दूसरा प्रस्ताव चंदन की लकड़ी के तेल के बारे में है जिसके संबंध में सभी मौजूदा छूटों को वापस लिया जा रहा है। इस प्रस्ताव से एक वर्ष में 30 लाख रुपए का नित्य लाभ होगा।

137. अब मैं उन परिवर्तनों की चर्चा करूँगा जिनसे राजस्व में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लोहे और इस्पात की मदों से संबंधित टेरिफ के वर्णनों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ जिनमें, जहाँ तक इन मदों का संबंध है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ का भारतीय सीमा-शुल्क टेरिफ के साथ ठीक मेल बैठ जाएगा। कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से अब तक अपनाए गए वर्गीकरण के सिद्धांतों को टेरिफ की प्रविष्टि में ही शामिल किया जा रहा है। लोहे और इस्पात से संबंधित टेरिफ को प्रविष्टियों को अधिक वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया जाएगा और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क लगाने के मामले में

आने वाली समस्याओं को भी काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। किन्तु इन परिवर्तनों को आवश्यक सैधारी करने के उपरान्त, बाद की तारीख में लागू किया जाएगा। तब तक, शुल्क की वर्तमान प्रभावी दरें लागू रहेंगी।

138. इन उपायों की शृंखला से कहीं ऐसा विचार न बन जाए कि वित्त मंत्री के प्रस्ताव केवल राजस्व जुटाने के लिए ही है, इसलिए मैं यह बतसा दूँ कि जहाँ कहीं उपयुक्त था, मैंने उत्पाद-शुल्कों में कुछ रियायतें देने का भी प्रयत्न किया है, जिनके बारे में मैं अब घोषणा करूँगा।

139. पारिवारिक बजट में चीनी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं 'लेवी' और 'लेवी-भिन्न' दोनों प्रकार की चीनी पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्तमान मूल्यानुसार दरों के स्थान पर मात्रानुसार दरें लागू की जाएंगी, अर्थात् 'लेवी' की चीनी पर 38 पैसे प्रति किलोग्राम और 'लेवी-भिन्न' चीनी पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दरें लागू होंगी। इससे एक पूरे वर्ष में 21.02 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी। किन्तु मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि चीनी पर बिक्री-कर के स्थान पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से राज्यों को मिलने वाली राशि में कोई कमी न हो।

140. अन्य देशों की तरह भारत में भी गृहणियां अपने व्ययों हुई वृद्धि के बारे में कुछ गमय से शिकायत कर रही हैं। वे जो कुछ पकाती हैं उसके पोषक गुणों को और आशा है उसकी स्वादिष्टता को भी किसी प्रकार प्रभावित न करते हुए, उनके ईंधन बिल में किराएत करने के एक उपाय के रूप में, मैं प्रेशर कुकरों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब वे अपने रसोई घरों में किमी और को भाप निकालता हुआ पाएंगी।

141. ईंधन की किराएत को बढ़ावा देने के इरादे से ही मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि कम ईंधन लगने वाले किरोमीन स्टोवों को पूरी तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया जाए।

142. इस समय 60 वाट तक के बिजली के बल्बों पर और फ्लोरोसेंट ट्यूबों पर क्रमशः 10 प्रतिशत मूल्यानुसार और 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की प्रभावी बुनियादी दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। इन मदों की कीमतों को कम करने के एक उपाय के रूप में और इस प्रकार कम लागत पर ज्यादा रोशनी फैलाने के प्रयत्न में सहायता देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पूर्णवत्त बल्बों को पूरी तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया जाए और उपरोक्त ट्यूबों पर बुनियादी शुल्क को 30 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए।

143. ईंधन की बचत के लिए बहु-धुरीय बालूनों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, मैं उन पर लगने वाले प्रभावी बुनियादी शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

144. किसान भाइयों के फायदे के लिए, जो इन उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को तथा क्षारीय भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि ग्रेड के पाइराइटों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए।

145. निचाई के लिए छिड़काव उपस्कर (स्प्रिंकलर) में काम आने वाली एल्यूमिनियम की पाइपों पर भी पूरी छूट दे दी जाएगी। इस समय इन पर 16 प्रतिशत मुल्यानुसार की दर से बुनियादी उत्पाद-शुल्क लगता है। एक दूसरा प्रस्ताव कृषि के काम आने वाले फुहारों (स्प्रेयर) और विद्युत शक्ति चालित साइकिलों के अन्तर्दहन इंजनों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने के लिए है।

146. तैयार या परिरक्षित खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों की कीमतों के ऊंचे होने का एक कारण यह भी है कि उनको पैक करने में इस्तेमाल किए जाने वाले धातुओं के डिब्बों (कंटेनर) की लागत का अंश भी उनकी कीमत में शामिल होता है। मैं इन भदों की उत्पाद-शुल्क के उस भाग से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसका सम्बन्ध ऐसे डिब्बों की लागत से हो। हमने उपभोक्ताओं के लिए इन खाद्य पदार्थों की कीमत में कमी आनी चाहिए।

147. एक किलोग्राम तक के पैक में बेचे जाने वाले मन्त्रनिया दूध के पाउडर को भी शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं के लिए उसकी कीमत कम हो जाए।

148. मैं अस्पतालों में काम आने वाले फर्नीचर की कई विनिर्दिष्ट भदों का शुल्क से पूरी छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ, जिससे अस्पतालों के लिए उनकी लागत कम हो जाएगी।

149. उत्पाद-शुल्क संबंधी इन रियायतों में राजकोष को एक पूरे वर्ष में 35.02 करोड़ रुपए की हानि होगी।

150. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों के संबंध में कुछ अन्य प्रस्ताव भी हैं जो अपेक्षाकृत मामूली हैं। मैं उनके बारे में सदन का समय नहीं लेना चाहता।

151. मैंने जो प्रस्ताव पेश किए हैं उनसे पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 409.00 करोड़ रुपए और सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 397.96 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। रियायतों और राहतों की राशि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 83.58 करोड़ रुपए और सीमा शुल्कों के अन्तर्गत 4.93 करोड़ रुपए बैठती है। इसलिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों में 325.42 करोड़ और सीमा-शुल्कों से 393.03 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय राजकोष को 589.71 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और राज्यों के हिस्से में 128.74 करोड़ रुपए आएंगे।

152. जिन मामलों में पहली माच 1983 से प्रवृत्त होने वाले परिवर्तन अधिसूचनाओं के जरिए लागू किए

जाएंगे, उनमें अधिसूचनाओं की प्रतिया सभा-पटल पर यथा समज रख दी जाएगी।

153. बजट प्रस्ताव बनाने में मुझे संसदीय समितियों की रिपोर्टों तथा आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा अब तक दी गई रिपोर्टों में की गई टिप्पणियाँ और सिफारिशों से बड़ी सहायता मिली है। जहाँ कहीं व्यावहारिक और समीचीन था, मेरे प्रस्तावों में इन सिफारिशों को मूर्तरूप दे दिया गया है, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा इन रिपोर्टों में की गई सभी सिफारिशों पर अंतिम रूप से निर्णय लेना सम्भव नहीं हुआ है। शहरी सम्पत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित अधिकरण की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में की गई कई सिफारिशों पर प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक के लिए कार्रवाई की जाएगी; इस विधेयक को तैयार करने का काम हाथ में लिया जाना है।

154. इस वर्ष मुझे अपने सम्मानित सहयोगी मंचार मंत्री जी की ओर से कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि उन्होंने अपनी बात स्वयं ही कह दी है। डाक सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इनका हर साल विस्तार किया जा रहा है। इस समय देश में 1,41,000 से अधिक डाक घर हैं और विभागेत्तर कर्मचारियों सहित लगभग 5.8 लाख कर्मचारी हैं। कार्यचालन की बढ़ती हुई लागत के कुछ भाग को पूरा करने के लिए डाक की शुल्क-दरों को संशोधित करना जरूरी हो गया है। मेरा पोस्ट-कार्डों और लैटर-कार्डों को छूने का विचार नहीं है, लेकिन पार्सलों से सम्बन्धित शुल्क-दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे कि एक पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपए और वर्ष 1983-84 में 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो सकेगी। प्रस्तावित शुल्क-दरों की जानकारी देने वाला एक शायन बजट पत्रों के साथ परिचालित किया जा रहा है। ये परिवर्तन संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित किए जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे।

155. मैंने पहले यह बताया था कि कराधान की मौजूदा दरों पर बजट में 2250 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। राहतों और रियायतों को हिसाब में लेते हुए, प्रस्तावित कर-उपायों से वर्ष 1983-84 में केन्द्र को 615.31 करोड़ रुपए और राज्यों को 100.74 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा, मैं पूँजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त करने के लिए अनुमोदित निवेश के रूप में जारी किए जाने वाले नए बांडों से होने वाली 135 करोड़ रुपए की प्राप्ति को भी हिसाब में ले रहा हूँ। मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों से प्राप्त होने वाले 55 करोड़ रुपए की, जिन्हें बजट में पहले ही शामिल किया जा चुका है, घटाने के बाद, इस संबंध में 80 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। इस प्रकार, बजट का घाटा कम हो कर 1555 करोड़ रुपए का रह जाएगा। सम्मानित

सदस्य इस यात से सहमत होंगे कि इसमें अर्थव्यवस्था पर कोई अनुचित दबाव नहीं पड़ेगा।

156. अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने विकास संबंधी जो समस्याएँ हैं, उनका कोई सरल समाधार अथवा सुगम मार्ग नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी सफलता अथवा असफलता अन्ततः हमारे आर्थिक प्रबन्ध के स्तर और जनता के सहयोग पर ही निर्भर करेगी। यह सच है कि हम चालू वर्ष में कृषि को धक्का लगाने के बावजूद कीमतों को स्थिर रखने, पिछले तीन वर्षों में अपनी राष्ट्रीय आय में लगभग 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करने और प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के बावजूद अपने भुगतान-शेष में कुछ सुधार करने में सफल हुए हैं। लेकिन इन उपलब्धियों से हम अपनी आर्थिक खुशहाली के भूलावे में न खो जाएं। अभी हमें लम्बा और कठिन रास्ता तय करना है, लेकिन अपनी जनता की सक्षमता और निष्ठा को देखते हुए, हम भविष्य का सामना आशा और विश्वास के साथ कर सकते हैं।

157. नरेंद्रा, अब मैं यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूँ।

ए० सी० तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

BUDGET 1983-84

Speech of

Minister of Finance

On 28th February, 1983

New Delhi, the 1st March, 1983

(Part A)

No. F. 15(1)-B(D)/83.—(1) I rise to present the Budget for the year 1983-84.

2. The Economic Survey for 1982-83, placed before the House a few days ago, has given a detailed account of the trends in Indian economy during the current year. I shall, therefore, be brief in reviewing the economic situation.

3. A drought year is always a difficult one for the economy. The decline in agricultural production that the drought entails has an effect which goes beyond the rural sector. The drop in the purchasing power of our farmers exerts a deflationary influence on industry. The drought also affects power generation and has an adverse impact on the external payments. It reduces the resource base and at the same time it calls for an increase in relief expenditure. The performance of the Indian economy in the year that is ending has to be viewed against this background. That we have come through it without too much damage to our productive structure and achieved remarkable success in containing price inflation is a tribute to the resilience of our economy. It also demonstrates the effectiveness of our policies of continued demand restraint and judicious supply management.

4. Although the growth in gross domestic product this year will be lower than it has been in the two previous years, we will achieve an average growth rate of nearly 5 per cent

over the three years, which is close to the target we set for ourselves in the Plan. At the same time, we have been able to maintain the tempo of investment. In other words, serious as has been the impact of drought, I believe we have not allowed it to affect the pace of development.

5. Let me now recapitulate the main highlights of the economic situation in 1982-83. On a point-to-point basis, the increase in the wholesale prices in the last week of January was 3 per cent compared with the annual rate of inflation of 5.7 per cent at the same time last year. The annual rate of increase in the consumer price index, as of December 1982, was also significantly lower 8 per cent as against 12.7 per cent in December, 1981. The lower rate of inflation this year is particularly noteworthy considering that wholesale prices had increased on an average by 2.4 per cent per month in June and July 1982 because of speculative pressures generated by the delay in the monsoon. However, as a result of an appropriate mix of demand and supply management policies, the situation was speedily brought under control.

6. Monetary policy continued to be deployed flexibly. The emphasis was on the need for restraint while at the same time it sought to meet productive requirements for credit. On the supply side, action was taken to build up stocks and improve availability of foodgrains through timely imports. Procurement efforts were stepped up so that the impact of a fall in the kharif output on stocks of foodgrains could be minimised. Higher releases of sugar and edible oils were also arranged. These and other supply management policies contributed significantly to the dampening of inflationary pressures after August 1982.

7. As I have so often emphasised in this House in respect of the price situation, there can be no room for complacency. The supply and demand situation in respect of sensitive commodities remains in delicate balance. While we have successfully weathered the immediate impact of the drought, we must remember that its effects are likely to be spread over a longer period than one season or one year. The international situation continues to be full of uncertainty and should there be a resurgence of inflation abroad, particularly in respect of commodities that we import, it could easily disturb our domestic price situation. We must also remain vigilant against anti-social elements, hoarders and black marketeers.

8. The kharif foodgrains production will be lower than last year because of adverse weather conditions. The indications, however, are that the rabi production may be somewhat better than last year. The output of cotton is likely to be close to the level of last year, while some decrease is expected in sugarcane and jute production. The target of 2.35 million hectares for increase in the irrigation potential in 1982-83 is likely to be achieved. While the agricultural sector continues to be influenced by the vagaries of the weather, over the long run, we have been able to increase output significantly and to reduce the disruptive effects of a drought on the economy. This has demonstrated the basic soundness of our agricultural strategy of extending the irrigated areas, encouraging the use of fertilisers and high yielding varieties, widening the credit network, and ensuring fair and remunerative producer prices for the major crops.

9. Industrial production increased by 8.6 per cent in 1981-82. In the current year, the increase is likely to be about 4.5 per cent. For the period, April to December 1982, impressive increases were recorded in respect of critical industries, such as crude petroleum, which increased by 30.6 per cent, cement

(10.2 per cent), fertilisers (9.6 per cent), and power generation (7.2 per cent). It is particularly heartening that thermal generation has shown substantial improvement and the plant load factor of thermal plants has also improved from 45.9 per cent during April—December 1981 to 47.6 per cent this year. Sugar production is expected to be close to the record level of last year. The overall rate of growth in industrial production was, however, adversely affected by a sharp drop in output of cotton cloth and yarn. Certain other sectors of industry also showed relatively low rates of growth because of slack demand or factors such as power constraints particularly in areas dependent on hydro-electricity.

10. Over the last thirty years, significant progress has been made in expanding and diversifying our industrial structure. The investment climate is highly favourable and capital issues during the year have reached a record level. However, in order to accelerate and sustain a higher growth rate of production, it is essential that the corporate sector should pay greater attention to improving its own rate of savings by better utilisation of capacity and economy in conspicuous and wasteful expenditure. In the increasing requirements of funds for investment we to be adequately met, the corporate sector must learn to look towards a larger volume of internal generation of resources. Borrowing can only supplement and not substitute corporate savings.

11. It is also essential to improve the productivity of past investments and reduce costs. Capital costs in the economy have increased, and due to delay in the implementation of projects, there is a decline in the returns that the community can legitimately expect from its investments. In respect of the public sector, the Government has initiated steps to monitor closely project implementation and operational efficiency. As Hon'ble Members are aware there has been a marked improvement in the working of many public sector enterprises though some units continue to face problems. Net profits of public sector units in the first nine months of this year increased to about Rs. 360 crores compared with Rs. 134 crores during the same period last year.

12. The process of building up the financial infrastructure continues apace. The banking system has been extending its coverage to the rural areas, more rural banks have been opened and the National Bank for Agriculture and Rural Development has commenced operations. All this would help to extend further the benefits of the institutional credit to the rural sector. Considerable progress has also been achieved in extending insurance to rural areas.

13. In the past few years, our balance of payments situation has been a matter of concern. In my budget speech last year, I had taken the opportunity to indicate the Government's strategy for restoring the viability in our balance of payments in the medium term. Briefly, the main elements of the strategy are to accelerate the pace of import substitution in critical sectors such as oil and fertilisers, to increase exports, and to improve the facilities available for remittances and investments by non-residents of Indian origin. The House would be happy to know that we have achieved considerable success in implementing this strategy.

14. The substantial increases in domestic production of petroleum and fertilisers have enabled us to reduce our dependence on imports of these items in the current year. Imports of steel, non-ferrous metals, and several other items have also been lower. Import policy has sought to combine the objective of reducing the growth of imports with the need to continue the liberal access to raw materials and capital goods for priority sectors. Tariff policies are being effectively

used to provide further protection to indigenous industries, wherever appropriate.

15. Exports, which increased by 16 per cent in 1981-82, have shown a further growth of 18 per cent in the first seven months of 1982-83. This is good performance considering the uncongenial external environment marked by rising protectionism, demand recession and near stagnation in world trade. The trade deficit is likely to be lower in 1982-83. The rate of decline in our reserves, excluding International Monetary Fund transactions, has also come down and has averaged Rs. 91 crores per month in this financial year up to end of January 1983 compared with Rs. 175 crores per month during 1981-82.

16. Our balance of payments adjustment has, however, been made more difficult by an unfavourable international environment characterised by lack of political will in industrialised countries for economic cooperation. It is necessary that in association with the developing and other non-aligned countries, we continue to work for basic reform in the international financial and trading system. India also has had to bear a disproportionate reduction in its share of concessional flows. In this situation, while recourse to a certain amount of commercial loans is unavoidable, we have to be extremely circumspect in relying upon this source as a means of financing current account deficits.

17. Hon'ble Members are aware of the geopolitical situation in the region and the increasing burden cast upon us because of the threat to our national security. No sacrifice is too great where the nation's security is concerned. At the same time, we cannot afford to slacken the development effort, however onerous the task may be, as in the ultimate analysis, the nation's security rests on its economic strength. Despite a difficult resource situation, I am happy to inform the House that we were able to achieve a substantial step up in the Plan outlay in 1982-83. The need for further economy and efficiency in the use of resources can hardly be over-emphasised. We must also continue to press ahead with additional resource mobilisation in a non-inflationary way.

18. Fiscal policy has an important role to play in the task of harnessing the nation's resources. In addition to appropriate adjustments in tax rates, the necessary administrative and legal measures are being taken to ensure that all sections of the community pay their taxes promptly. This Government is determined to plug avenues for tax evasion and avoidance, and to continue the fight against economic offences.

19. Raising the living standards of our people is possible only through a progressive increase in savings and productivity. The Indian people, we must gratefully acknowledge, have set standards of saving levels remarkable for a low income country. It is, however, essential that these savings are invested in assets which add to productive capacity and which directly benefit the people.

20. In the past three years, several steps have been taken to encourage the savings habit. The interest rate mechanism and the fiscal instrument have been used to provide an attractive return on savings in the form of financial assets. In line with the decision to raise the interest rate on 5 year bank deposits, announced in October last year, it has been decided to increase the rate of interest on 5-year Post Office Time Deposits and Recurring Deposits from 10.5 per cent to 11.5 per cent per annum. Similarly I propose to increase the rate of interest by 1 per cent on Special Deposits of Employees Provident Fund and other non-Government provident, gratuity

and superannuation funds. The improvement in the rate of return on these deposits would benefit workers and small savers.

21. I also propose to liberalise the Public Provident Fund Scheme, which has become increasingly popular among self-employed and others. Subscribers will be allowed to continue their accounts beyond 15 years. The limit for annual subscription is also being raised to Rs. 40,000.

22. In the light of the changes that have taken place in the monetary and economic situation in the last two years, the Government, in consultation with the Reserve Bank of India, has reviewed the interest rates on advances by commercial banks. It has been decided to reduce the ceiling rate of interest from 19.5 per cent to 18 per cent. The structure of interest rates is also being adjusted downwards for the benefit of agriculture, small scale industry and exports. A separate announcement in this respect is being made by the Reserve Bank of India.

23. The Government has provided liberal incentives for attracting remittances and investments by non-residents of Indian origin. In the light of the experience, it has been decided to improve further the facilities available to non-residents. Last year I had announced certain important concessions in respect of subscriptions by the non-residents to 6-Year National Savings Certificates, which carry interest at 12 per cent per annum. In order to further improve their yield, I propose to allow an additional interest of one per cent on these certificates if these are subscribed for in foreign exchange. I also have some other important proposals to which I shall refer later. I am sure that the House will agree with me that our policy frame-work meets the requirements of non-residents, and that we can look forward to further strengthening of the bonds that exist between them and this country.

24. I shall now turn to the Revised estimates for 1982-83 and the Budget estimates for 1983-84.

Revised Estimates for 1982-83

25. The Budget estimate for the total expenditure in 1982-83 was Rs. 29,219 crores of which Rs. 11,315 crores was on Plan account and Rs. 17,874 crores on non-Plan account. As the year progressed, it became evident that we would need to enhance both these broad categories of expenditure. Despite the strains imposed on the economy by natural calamities, it has been our endeavour that outlays in respect of long-term development should not be allowed to suffer. One of my highest priorities, therefore, has been to protect the Plan and, in the result, the Revised estimates for Central Plan outlay are Rs. 603 crores higher than those originally budgeted.

26. Railway Plan outlay has been increased by Rs. 195 crores, of which budgetary support will account for Rs. 105 crores. The budgetary support for the power sector will go up by Rs. 62 crores, while assistance to National Bank for Agriculture and Rural Development has been increased by Rs. 100 crores. The outlays for schemes of family welfare have been enhanced by Rs. 50 crores. Plan provisions for rural water supply, agriculture and co-operation have also been stepped up, while the budgetary support for the Posts and Telegraphs Plan has been increased by Rs. 75 crores owing, in this case, to a shortfall in internal resources. As against these increases, some reductions

are expected in relation to Budget estimates of Plan expenditure in a few sectors. Overall, the budgetary support for the Central Plan is estimated to go up by Rs. 262 crores to Rs. 7605 crores.

27. The Central assistance for State and Union Territory Plans is also being stepped up by Rs. 380 crores, of which Rs. 350 crores is the additional advance Plan assistance to States which have been affected by drought.

28. Non-Plan expenditure will also be higher in the current year due to several factors. Non-Plan grants to States will be higher by Rs. 214 crores mainly due to additional assistance of Rs. 147 crores for States affected by floods, cyclones and other natural calamities. Similarly, reflecting the buoyancy in small savings collections, non-Plan loans to States, on this account will be higher by Rs. 200 crores. Non-Plan loans for agricultural inputs have also been increased by Rs. 50 crores. The subsidy for indigenous fertilisers will go up by Rs. 200 crores. Additional loans of Rs. 209 crores are required for certain public sector undertakings to enable them to meet their cash losses and interest and repayment obligations to the Government.

29. The provision for Defence expenditure will be higher by Rs. 250 crores. To meet the temporary imbalance in the trade covered by Rupee Trade Agreements, the provision for Technical Credits has to be increased from Rs. 80 crores to Rs. 1280 crores. The increase in Technical Credits has been due to temporary and exceptional circumstances, and will be largely reversed during the year. Hon'ble Members will appreciate that in a year of weak global demand, our long standing trading relationship with the Socialist countries has been an important element in providing a measure of stability to our export sector.

30. Excluding the loan of Rs. 1743 crores to States, to which I shall refer later, the total non-Plan expenditure is likely to go up from Rs. 17,874 crores to Rs. 20,511 crores.

31. Coming to receipts, as I mentioned at the beginning the drought inevitably affects the income and resource base of the economy. Despite these adverse effects, the Budget estimates of receipts from Income-tax and Customs duties are expected to be realised. However, receipts from Union excise duties may show a shortfall of Rs. 220 crores. Apart from the impact of a lower growth in industrial production, there has been locking up of some revenues due to pending litigation. Some shortfall in Corporation tax is also anticipated. The Centre's net tax revenue after paying the States' share of taxes, is estimated at Rs. 13,271 crores as against the Budget estimate of Rs. 13,362 crores.

32. Non-tax revenue is, however, expected to show an improvement of Rs. 613 crores mainly due to larger dividend payment by Railways, larger receipts from some public sector units, recovery from the Indian Dairy Corporation of the value of gift material supplied to it earlier and larger external grants.

33. Capital receipts are also estimated to go up from Rs. 10,249 crores to Rs. 12,446 crores. Receipts from market loans are estimated at Rs. 3800 crores against the Budget estimate of Rs. 3200 crores. As mentioned earlier, the recovery of Technical Credits will also go up from Rs. 90 crores to Rs. 1080 crores. The receipts from small savings are estimated to go up by Rs. 150 crores.

34. The total receipts are thus estimated to go up from Rs. 27,844 crores to Rs. 30,563 crores.

35. Taking into account the above and other variations in receipts and expenditure, the budgetary deficit in the current year is now estimated at Rs. 1935 crores. This excludes the special loan assistance to States of Rs. 1743 crores, which does not have any economic impact in the current year. The larger deficit over Budget estimates in the current year has to be viewed against the background of weak demand in certain sectors of the economy. That is has not had a destabilising effect on the economy has been demonstrated by the price behaviour in recent months.

Budget Estimates for 1983-84

36. In framing the next year's Budget, Mr. Speaker, Sir, my aim has been to provide for a large increase in the Plan outlay so that the pace of development, which we have assiduously built up, is not retarded. Even this increase, I am acutely aware, cannot be expected to fully meet the demand from various sectors, however pressing they may seem. Some reordering of priorities among different objectives and sectors has, therefore, become necessary.

37. I propose to increase the Central Plan outlay to Rs. 13,870 crores in 1983-84 inclusive of a special allocation of Rs. 300 crores to which I shall refer later. This constitutes an increase of 26.1 per cent over the Plan outlay of Rs. 11,000 crores in the Budget estimates for 1982-83. Coming on top of an increase of 27.6 per cent provided in the Budget for 1982-83, the proposed increase would enable us to meet our urgent requirements in critical sectors of the economy, and also provide a special thrust in respect of programmes meant for the welfare of the weaker sections of the society. The Central Plan will be financed by a budgetary support of Rs. 8390 crores and internal and extra-budgetary resources of Rs. 5480 crores.

38. Hon'ble Members are aware that the finances of several States have been under severe strain for some time. While the need for fiscal discipline cannot be over-emphasised, an important objective of the Central Government has been to ensure that, despite resource constraints, the State Plans also show a reasonable order of increase. Hon'ble Members would recall that in June 1982, I decided to clear States' closing deficits of the previous year with a medium term loan of Rs. 1743 crores. I did so to help the States to re-adjust their finances and achieve adequate investment in their plans. In the current year, the Centre has provided nearly Rs. 700 crores of assistance to States for drought and flood relief. Further, we have decided to increase Central assistance to States in the next two years by Rs. 1650 crores over the balance available in the originally approved level. This will augment the Plan resources of the States. The States have responded by agreeing to enhance their resource mobilisation efforts.

39. The total Plan outlay for 1983-84 of the States and Union Territories is now placed at Rs. 11,625 crores. This represents an increase of 16.4 per cent over the finally approved outlay of Rs. 9989 crores in 1982-83, the highest increase so far in the current plan period. Central assistance for the Plan of the States and Union Territories will be Rs. 4462 crores.

40. Taken together, the Plan outlays of the Centre, States and Union Territories for 1983-84 will be Rs. 25,495 crores, an increase of 21.5 per cent over the finally approved outlay of Rs. 20,989 crores in 1982-83.

41. In formulating the 1983-84 plan, our primary concern has been to provide maximum support to those projects and programmes which can be of immediate benefit to the economy, and especially to the weaker sections of society. The outlays for the Revised 20-Point Programme have been enhanced, and a special thrust is being given to programmes that benefit the poor directly.

42. I have also taken the somewhat unconventional step of providing an additional Rs. 300 crores over and above Rs. 13,570 crores set apart specifically for the various schemes in the next year's Central Plan. This amount will be provided as grants to the States on the basis of their better performance in implementing specific programmes. These programmes will benefit the weaker sections of the community and improve the functioning of the State Electricity Boards. The Co-operation of the States is essential and, wherever appropriate, the guide-lines to be issued, would provide for matching contributions by them.

43. Out of this allocation, I am earmarking Rs. 125 crores to assist small and marginal farmers to improve the productivity of their land. My colleague, the Minister of Agriculture, will be announcing the details of the scheme.

44. Another Rs. 125 crores would be distributed among the States on the basis of their performance in implementing programmes in identified areas of high priority, which the Government will announce later. The assistance for these purposes would be made available only to those States which demonstrate capacity to achieve targets over and above those implied in their approved Plans. I

45. I have had occasion in the past to underline the importance of obtaining maximum returns out of existing investments. The need for increasing the plant load factors in thermal power stations cannot be over-emphasised. I, therefore, propose to set apart the balance of Rs. 50 crores out of Rs. 300 crores for incentive payments to State Electricity Boards for better performance. Most of the State Electricity Board achieved their peak plant load factors during the years 1975-77. Unfortunately, their recent performance has fallen far short of these levels. I hope that this incentive would encourage the State Electricity Boards to reach and even surpass their earlier peaks.

46. Apart from the above special allocation, the outlay for the 20-Point Programme in the Central Sector Plan for 1983-84 is Rs. 2747 crores representing an increase of 26.8 per cent over the outlay in the current year's Plan. The provision for these schemes in the approved Plan outlay of the States and Union Territories for 1983-84 will be Rs. 7332 crores. Hon'ble Members will be happy to know that the total provision for 20-Point Programme next year will thus exceed Rs. 10,000 crores.

47. Next year's programme also provides a high priority to agricultural development. The total outlay for this sector is Rs. 608 crores. This includes Rs. 200 crores for the National Bank for Agriculture and Rural Development. Two main programmes, one for oil seeds development and another for dry land farming, both important elements in the 20-Point Programme, will also be taken up for implementation in 1983-84. Further, a sum of Rs. 800 crores is being provided for agricultural programmes in the approved Plan outlay of the States and Union Territories. The outlays for irrigation and flood control are also being stepped up to Rs. 116 crores in the Central Plan and Rs. 2404 crores in the Plans of the States and Union Territories.

48. The outlay for the National Rural Employment Programme, Integrated Rural Development Programme and other schemes of the Ministry of Rural Development would be Rs. 480 crores in 1983-84 against the likely expenditure of Rs. 419 crores in 1982-83. The I.R.D.P. will enable about three million families in the rural areas to cross the poverty line. The N.R.E.P. will create about 350 million man-days of work in the rural areas. The provisions for these programmes will be matched by the State Governments.

49. Hon'ble Members are aware that the Government has launched a crash programme for providing drinking water facilities in all problem villages. The Plan outlay for 1982-83 visualised an allocation of Rs. 127.5 crores by the Centre for the accelerated rural water supply programme. Having regard to the progress in implementation the outlay has now been increased to Rs. 155 crores. A substantially higher outlay of Rs. 200 crores has been provided for this programme in 1983-84. The States on their part will be setting apart Rs. 319 crores and in all 48,000 more villages are expected to be covered in 1983-84.

50. One of the important programmes benefiting children is the Integrated Child Development Services. With the higher target now set for the Sixth Plan, it is proposed to extend this scheme to 200 more projects, in 1983-84 over and above the 620 projects so far covered. Over half the total provision of Rs. 60 crores for Department of Social Welfare will be accounted for by this scheme.

51. An increased provision of Rs. 176 crores has been made in the Central Plan for 1983-84 for the various programmes benefiting the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

52. The Family Welfare Programmes will be implemented with renewed vigour in 1983-84 and will cover 17 million persons. A sum of Rs. 330 crores is being provided for these programmes.

53. The Sixth Plan has placed considerable emphasis on accelerating investment in the Energy sector. The total outlay for this sector covering petroleum, power and coal would be Rs. 5014 crores, accounting for more than 36 per cent of the total Central Plan outlay. Crude oil production is expected to reach 21 million tonnes this year, and increase further to around 26 million tonnes in 1983-84.

54. Inclusive of the allocation for power development under Atomic Energy and Coal, the total outlay for the various power programmes in 1983-84 in the Central Plan will be Rs. 1222 crores, representing an increase of 31.5 per cent over that for 1982-83. The target for addition to the capacity in 1983-84 in the Central Sector will be 1050 MW, double that of the current year.

55. The outlay for Coal sector, including lignite, will be Rs. 946 crores in 1983-84. The target for production of coal is 142 million tonnes, 9 million tonnes more than in the current year.

56. The provision for the various programmes of the Department of Steel in the Plan for 1983-84 is Rs. 820 crores. The Plan outlay of the Mines Department has been increased to Rs. 494 crores in 1983-84 compared to Rs. 292 crores in the current year's approved Plan outlay. This includes Rs. 365 crores for the Orissa Aluminium Project.

57. The revenue earning traffic to be carried by the Railways in 1983-84 is projected at 241 million tonnes, which is an increase of more than six per cent over the likely performance

in 1982-83. The Plan outlay for the Railways in 1983-84 is Rs. 1342 crores.

58. The traffic handled at the ports is expected to increase to 105 million tonnes in 1983-84 as against 95 million tonnes likely to be reached in 1982-83. Inclusive of a provision of Rs. 90 crores for the Nhava Sheva Project, and Rs. 40 crores for investment in State Road Transport Corporations, a total outlay of Rs. 558 crores has been set apart for the Shipping and Transport Ministry in 1983-84.

59. An outlay of Rs. 429 crores has been provided for the various projects of the Ministry of Chemicals and Fertilizers. This includes Rs. 260 crores for the Thal Vaishet Fertilizer Project. For the Hazira Fertilizer Project a provision of Rs. 145 crores has been made.

60. The total provision for the projects of the Ministry of Industry in 1983-84 is Rs. 549 crores compared with Rs. 480 crores in the current year. Of this, the provision for small industries, including KVIC and coir, is about Rs. 173 crores.

61. A provision of Rs. 72 crores has been made for the various Plan programmes of the Department of Science and Technology and the Council of Scientific and Industrial Research in 1983-84. The Government has recently set up a separate Department of Non-Conventional Energy Sources. The programmes to be undertaken by this Department in 1983-84 would include, inter alia, establishment of 75,000 family size bio-gas units and 100 community bio-gas units. Inclusive of the provision of Rs. 18 crores for the bio-gas programme, an outlay of Rs. 30 crores has been set apart for this Department in the Plan for 1983-84.

62. Mr. Speaker, Sir, it has been my effort to contain the growth in the non-Plan expenditure. However increases in certain important sectors have been inevitable. Taking into account the requirements of the country's defence, a provision of Rs. 5971 crores has been made for Defence against Rs. 5350 crores in the Revised estimates for the current year. Due to increase in borrowings which are mainly used for development purposes and also higher borrowing costs, the provision for interest is placed at Rs. 4700 crores against Rs. 3950 crores in the Revised estimates for the current year. The provision for food subsidy at Rs. 800 crores will be higher by Rs. 90 crores compared with the Revised estimates for the current year. The provision for subsidy on indigenous fertilisers is estimated to go up from Rs. 550 crores in the current year to Rs. 700 crores next year. A provision of Rs. 550 crores has been made for cash compensatory support and market development assistance for exports.

63. The provision for Technical Credits under Rupee-Trade Agreements is Rs. 600 crores next year as against Rs. 1280 crores in the current year. A lump sum of Rs. 300 crores is being provided in 1983-84 for payment of additional instalments of dearness allowance, pension and other reliefs to Central Government employees.

64. The House would recall that last year, I had announced certain enhanced benefits for low paid pensioners. I propose to provide some additional relief to this category of pensioners. From 1st April, 1983, the minimum amount of pension, including dearness relief, will be raised to Rs. 160 per month and the minimum amount of family pension including dearness relief to Rs. 150 per month.

65. The total non-Plan expenditure in 1983-84 is estimated at Rs. 21,984 crores against Rs. 20,511 crores in Revised estimate 1982-83.

66. At this point, I would like to refer to a matter concerning Government employees. The employees had suggested some time ago that the Government may appoint a Pay Body for revising pay scales. The Third Pay Commission was appointed in April 1970 and made its report in 1973. Since then, over the years conditions have changed in several respects. The employment under the Central Government has grown steadily larger. Changes have also taken place in the relativities in the emoluments of the employees of departments inter se, and also vis-a-vis other employees. For instance, several State Governments have, through Pay Committees or Pay Commissions, substantially revised the pay scales and other benefits of their employees. I feel it would be appropriate now to appoint the Fourth Central Pay Commission. Before the terms of reference of the Pay Commission are settled, the representatives of the employees would be consulted. The membership of the Commission together with the terms of reference will be announced as soon as possible.

67. So far as receipts in 1983-84 are concerned, the gross tax revenues at the existing rates of taxation are estimated at Rs. 19,964 crores compared with Rs. 17,910 crores in the Revised estimates. The States' share of taxes in 1983-84 is estimated at Rs. 5088 crores compared with Rs. 4639 crores in the current year. The net tax revenue of the Centre will thus be Rs. 14,876 crores against Rs. 13,271 crores in the current year.

68. The receipts from market loans are placed at Rs. 4000 crores compared with Rs. 3800 crores in the current year. The recoveries of Technical Credits next year will be lower as the payments will also be less. Small savings collections are expected to yield Rs. 1700 crores next year against Rs. 1550 crores this year. External assistance net of loan repayments, is estimated at Rs. 1940 crores against Rs. 1724 crores in the current year.

69. Taking into account these and other variations in receipts, the total receipts for 1983-84 are estimated at Rs. 32,586 crores. These receipts include the effect of the changes in fare and freight rates of the Railways and in the Posts and Telegraphs tariffs as well as the continuance of the Compulsory Deposit Scheme for Income-tax payers beyond 31st March, 1983, to which I shall refer later. The total expenditure is placed at Rs. 34,636 crores. The overall budgetary gap at existing rates of taxation will thus be Rs. 2250 crores.

(Part B)

70. Mr. Speaker, Sir, it is against the background of this review of budgetary out-turn that I place my budget proposals before Hon'ble Members. The Budget is more than an exercise in raising revenue or financing outlays. In a planned economy, it represents a potent instrument for achieving national objectives and sustaining the pace of development through appropriate financial and fiscal policies. I would, therefore, like to share with Hon'ble Members the philosophy of my budget. It aims at strengthening the productive forces in the economy, keeping a tight rein on inflation, encouraging savings both in the individual and corporate sectors

and promoting essential investment. The encouragement of savings has its corollary in discouraging consumption. Conspicuous consumption whether at individual or the corporate level has no place in a society such as ours. I have also taken this opportunity to review the effects of certain incentives and concessions in the tax law, and to modify them where appropriate. As we are placed now, the Budget must reflect the imperatives of attaining as speedily as possible a viable external payment situation and, therefore, seek to promote exports and affect economies in imports through a judicious use of the fiscal instrument.

71. Within this overall framework, it has been my objective to keep the budgetary deficit for the next year relatively low. While it has been necessary to raise additional resources, I have tried to do so in a non-inflationary way and without subjecting the low and middle income groups to additional burdens.

72. I shall first deal with my proposals in the area of non-corporate income taxes. My aim is to provide some relief at the lower end of the slabs and specially to the salaried taxpayer. At the same time, it has been my endeavour to promote savings at the expense of consumption. With this end in view I am providing for a more liberal application of the exemptions pertaining to savings.

73. Coming to my specific proposals let me begin with the unpleasant bit. I propose an increase in the surcharge in the income-tax on non-corporate taxpayers from the present level of 10 per cent to 12.5 per cent. The revenue yield from this measure would be Rs. 47 crores in a full year and Rs. 37.6 crores in 1983-84. This will accrue wholly to the Centre. Considering the increased burden cast on the Centre on account of additional expenditure on national security and special assistance to the States, Hon'ble Members will agree that this measure is justified.

74. Now for the good news. As a measure of relief to the salaried taxpayer I am proposing that the ceiling of standard deduction be increased from the present Rs. 5,000 to Rs. 6,000. The revenue loss as a result of this proposal is expected to be Rs. 19 crores in a full year and Rs. 15.2 crores in 1983-84.

75. In recent years we have increased the exemption limits in respect of income-tax. It has, however, been pointed out to me, with some justification, that the tax rate in the initial slab is somewhat high. I accordingly propose to split the initial slab, and for the first slab between Rs. 15,001 and Rs. 20,000 the tax rate will be 25 per cent instead of 30 per cent. The present rate of 30 per cent will, however, continue to apply to the slab Rs. 20,001 to Rs. 25,000. For the next slab between Rs. 25,001 and Rs. 30,000 the rate will be raised by 1 percentage point to 35 per cent. Even after the increase in rate of surcharge, individuals and certain categories of Hindu undivided families, etc. in the lower income slabs will pay less tax than at present. The revenue effect of these proposals would be a loss of Rs. 35 crores in a full year and Rs. 28 crores in 1983-84.

76. As a measure to stimulate savings, I propose to remove the ceiling of 30 per cent of gross total income in respect of savings in specified forms like life insurance, provident funds, etc., while retaining the absolute monetary ceilings. Further, I intend widening the available media for savings by including National Savings Certificates, VI and VII Issues. This would be particularly helpful to those past middle age

and towards the end of their working lives who might find it difficult to take advantage of life insurance and other contractual forms of savings. The revenue loss from this measure is expected to be Rs. 15 crores in a full year and Rs. 12 crores next year.

77. Income derived from specified long-term investments is exempt at present up to Rs. 4,000 with an additional exemption of Rs. 2,000 for interest on securities and bank deposits for a period exceeding one year. As a measure of simplification, I propose to merge these separate exemption limits and raise it from Rs. 6,000 to Rs. 7,000. The existing separate exemption of Rs. 3,000 in respect of income from units of the Unit Trust of India will continue unchanged. As a result of these proposals, the aggregate of specified investment income which is exempt from tax would go up from Rs. 9,000 to Rs. 10,000. This should help to stimulate savings further.

78. Hon'ble Members would appreciate that in sum the effect of the above proposals would be such as not to increase the tax liability of assessee in the lower brackets of the tax scale notwithstanding the increase in the surcharge. As for the rest, as I intend the surcharge primarily to affect consumption rather than savings I have sought to combine the surcharge with measures designed to increase personal savings in specified financial assets.

79. I propose to extend the operation of the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974, by a period of two years. At present, persons over 70 years of age are exempted from the requirement of making deposits. I propose to lower this limit from 70 to 65 years. Those who attain the age of 65 years on 1st April, 1983, would be entitled to withdraw, at their option, the balance of the deposits to their credit, on or after 1st June, 1983.

80. At present no tax on capital gains is charged in cases where the net consideration received on transfer of a capital asset is invested in 7-year National Rural Development Bonds. It has been pointed out to me that this maturity period is rather long. In order to provide investment choices and with a view to ensuring that resources flow into desired directions, I propose to extend the exemption to cover investment of the net consideration in a new Central Government Bond of 3 years' maturity, a special series of units of the Unit Trust of India and debentures of the Housing and Urban Development Corporation with maturity periods adjusted appropriately for the interest they carry.

81. As I indicated earlier, I have decided to liberalise further the tax incentives in respect of non-resident Indians investing in India. I propose to levy a flat rate of tax of 20 per cent plus surcharge on incomes derived by such persons from their specified investments in India made through foreign exchange remittances. These investments will include shares and debentures of Indian companies, units of the Unit Trust of India and Government securities. Long-term capital gains arising on transfer of such assets will also attract tax at the proposed flat rate. Such incomes will also not be taken into account in computing their other Indian incomes. They would not have to go through the procedures involved in submission of tax returns, provided they have no other income in India and tax at the proposed flat rate has been deducted from their income. These non-residents will also have the option of paying tax at the normal rates applicable to resident taxpayers. Such investments will also be exempt from

wealth-tax. Gifts of such assets made by Indian citizens and persons of Indian origin settled abroad to their relatives in India will also be exempt from gift-tax.

82. I shall now deal with my proposals in respect of the corporation tax. Earlier in my speech I had referred to the need to accelerate investment through higher internal generation by companies and curbing conspicuous consumption. I believe that both the Government and the companies can contribute towards this objective.

83. It has been pointed out to me by several committees and representative organisations of industry that given the rising costs of replacement and modernisation, the internal funds available with the corporate sector are inadequate. I find substance in this argument. Accordingly, I propose to increase the general rate of depreciation in respect of plant and machinery from 10 per cent to 15 per cent. I am also raising the monetary limit for 100 per cent write-off from the present level of Rs. 750 to Rs. 5,000 in respect of small items of plant and machinery. The other related benefits which new investment in plant and machinery now enjoy will continue. The revenue loss on account of liberalisation of provisions relating to depreciation would be Rs. 140 crores in a full year and Rs. 112 crores in 1983-84.

84. Hon'ble Members would recall that last year I had proposed to allow depreciation at 30 per cent of the cost of devices and systems for energy savings and for minimising environmental pollution and for conservation of natural resources. I propose to go farther and allow 100 per cent depreciation on devices and systems for energy saving. In regard to devices and systems for minimising environmental pollution and for conservation of natural resources, I propose to raise the investment allowance from 25 per cent to 35 per cent.

85. To encourage industries to shift from urban areas and as a measure of decongesting our overcrowded cities and reducing pollution, the capital gain arising from transfer of buildings or lands used for the purposes of business is exempt from tax if it is used for acquiring lands or constructing buildings for the purposes of business at the new place. I propose to extend this exemption from tax to capital gain arising from transfer of machinery and plant also.

86. I have occasion earlier to refer to the lowering of the interest rate structure. As my contribution to the relief being provided by banks and with a view to encouraging production and investment, I propose to reduce the rate of tax charged under the Interest-tax Act to half of the prevailing rate. In respect of the chargeable interest arising after 31st March, 1983, the rate of interest-tax will be reduced from seven per cent to three and a half per cent. About half of the loss of Rs. 130 crores on account of this measure will be recouped by the additional tax revenue as a consequence of the lower deductible cost of borrowing to business and industry.

87. My other important objective in respect of the corporate tax structure is to provide incentive for higher production and exports. I am, therefore, continuing the two schemes announced last year and making them more liberal.

88. As regards the scheme for excess production, I will come to the details later while discussing my proposals in respect of indirect taxes.

89. In respect of exports the scheme announced by me last year provided some tax relief to exporters whose export turnover for any year exceeded that of the immediately preceding year by more than 10 per cent. The total relief available under last year's scheme was also subject to a maximum of 10 per cent of tax payable. I now propose to simplify and liberalise the scheme and remove both the minimum qualifying amount and limit of relief. Exporters will be entitled to deduct 5 per cent of their incremental turnover in computing their taxable income. Thus, under the new scheme all increments in export turnover will be entitled to relief. Exports of all goods will qualify for this concession excepting a few specified items. As the new provision will take effect from the assessment year 1983-84, the provision made last year is proposed to be deleted.

90. Hon'ble Members must be aware of the phenomenon of companies which are flourishing, but are paying no tax at all, or only a nominal tax. This is largely due to these companies availing of the tax incentives and concessions available under the provisions of the Income-tax Act. It has been a matter of concern to me that under our tax system several highly profitable companies are able to reduce their tax liability to zero even though they continue to pay high dividends. It seems reasonable that profitable and prosperous companies should contribute at least a small portion of their profits to the notional exchequer at a time when other and less better off sections of society are bearing a burden. I therefore propose to provide that fiscal incentives and concessions shall not absorb more than 70 per cent of the profits. This would secure that companies pay a minimum tax, on at least 30 per cent of their profits.

91. The differential rates of tax in the case of domestic companies depending upon the total income of the company are proposed to be removed.

92. As a measure of simplification, I propose to levy income-tax at a flat rate of 25 per cent on the gross amount of interest received by foreign companies on loans advanced by them in foreign currency.

93. The income-tax payable by companies at present bears a surcharge of 2.5 per cent of such income-tax. I propose to raise the rate of surcharge to 5 per cent. However, in lieu of the additional surcharge payable by them, companies will be offered the option to make deposits with the Industrial Development Bank of India under a scheme to be notified by the Government. I am not taking credit for any revenue gain from this measure in the expectation that the additional surcharge would, in fact be deposited by the companies with Industrial Development Bank of India. The amount so deposited should help to provide funds for modernisation and thus flow back to the corporate sector.

94. Our corporate tax structure is riddled with a large number of different kinds of deductions. While each deduction may seem to have a merit, the aggregate effect is to complicate tax administration, provide opportunities for misuse and reduce the growth of revenues. As a step towards rationalisation of this structure, I have reviewed the various deductions.

95. The Income-tax Act at present provides for weighted deduction of expenses incurred by a company or a co-operative society which uses products of agriculture, animal husbandry, dairy or poultry farming as raw material. The

expenses in respect of which weighted deduction is allowed do not relate directly to the assessee's business. I propose to provide that such companies or co-operative societies would henceforth be entitled only to the deduction of expenses and not to the weighted deduction.

96. The Income-tax Act provides deductions for expenditure or contributions made by assesseees for approved programmes of rural development. On going programmes approved by the prescribed authority will continue to enjoy the benefits of the deduction upto the terminal date in respect of time bound programmes and February 29, 1984 in other cases. However, with a view to preventing possibility of misuse, it is proposed not to allow any further deductions on this score. It is not the intention of the Government to deprive genuine rural development programmes of corporate support. The Government would shortly establish a fund called the Prime Minister's Fund for Rural Development, contributions to which would enjoy exemption under the Income-tax Act.

97. The special deduction allowed hitherto in respect of profits and gains from business of livestock breeding or poultry or dairy farming and from business of growing mushrooms, is proposed to be withdrawn. I see little justification for continuing this fiscal concession to these businesses, in view of the room for abuse. However, in order to encourage and strengthen primary co-operatives for oil-seeds, fruits and vegetables, I propose to provide full exemption from tax for such co-operatives as in the case of dairy co-operatives.

98. The tax concession in relation to horizontal transfer of technology was introduced in 1969. The objective was to discourage repetitive import of foreign technology. I find that the concession has lent itself to be used for tax avoidance. I, therefore, propose to withdraw this concession effective from assessment year 1984-85.

99. Hon'ble Members must be aware of lavish and wasteful expenditure by trade and industry, particularly on traveling, advertisement and the like. With a view to inculcating a climate of austerity and providing a disincentive to unproductive, avoidable and ostentatious spending by trade and industry I propose to provide that 20 per cent of such expenditure will be disallowed in computing the taxable profits. The Income-tax Act provides for the disallowance of entertainment expenses beyond a ceiling and for total disallowance of expenses on maintenance of guest houses. I propose to define the terms "entertainment expenditure" and "guest house" to remove doubts about the correct import of these expressions. The revenue from these measures in a full year will be Rs. 50 crores and in 1983-84 Rs. 40 crores. The effect of these measures, combined with the increase in depreciation allowance, will be to provide a marked preferential tax treatment of investment as against unproductive expenditure.

100. Several cases have come to notice where taxpayers do not discharge their statutory liability such as in respect of excise duty, employer's contribution to provident fund, Employees' State Insurance Scheme, for long period of time. For the purpose of their income-tax assessments, they nonetheless claim the liability as deduction even as they take resort to legal action, thus depriving the Government of its dues while enjoying the benefit of no-payment. To curb such practices I propose to provide that irrespective

of the method of accounting followed by the taxpayer, a statutory liability will be allowed as a deduction in computing the taxable profits only in the year and to the extent it is actually paid. This would result in a revenue gain of Rs. 100 crores in a full year and Rs. 80 crores in 1983-84.

101. It has come to my notice that some persons have been trying to avoid personal wealth-tax liability by forming closely-held companies to which they transfer many items of their wealth, particularly jewellery, bullion and real estate. As companies are not chargeable to wealth-tax, and the value of the shares of such companies does not also reflect the real worth of the assets of the company, those who hold such unproductive assets in closely-held companies are able to successfully reduce their wealth-tax liability to a substantial extent. With a view to circumventing tax avoidance by such persons, I propose to revive the levy of wealth-tax in a limited way in the case of closely-held companies. Accordingly, I am proposing the levy of wealth-tax in the case of closely-held companies at the rate of 2 per cent on the net wealth represented by the value of specified assets, such as, jewellery, gold, bullion, buildings and lands owned by such companies. Buildings used by the company as factory, godown, warehouse, hotel or office for the purposes of its business or as residential accommodation for its low-paid employees will be excluded from net wealth.

102. The sum of my proposals in respect of the corporate sector the Hon'ble members would appreciate, is to ensure that every profitable company pays some tax in the year in which profits accrue, that loopholes are plugged and the number of deductions is reduced, that more funds are available for modernisation and re-investment, that costs are reduced through lower interest charges and reduction in conspicuous expenses, and that higher production, particularly for exports, receives due encouragement.

103. Many charitable and religious trusts and institutions no doubt do laudable work. Unfortunately, it is also true that many are used as a medium for tax avoidance, accumulation of wealth and means of patronage and I cannot remain a disinterested spectator. It is time some steps were taken to set matters right.

The Taxation Laws (Amendment) Act, 1975 had laid down an investment pattern for trust funds, and trusts which failed to comply with this investment pattern from accounting years commencing after 31st March, 1978 were liable to forfeit tax exemption. However, having regard to the practical difficulties involved and to ensure a more orderly change-over, this date was extended in 1977 by three years. As the whole gamut of the provisions relating to charitable and religious trusts was under consideration by the Economic Administration Reforms Commission, the date for the new pattern of investment was again extended last year by a further period of one year.

I have since considered the matter carefully. I see no justification for permitting investment of trust funds in business concerns, including shares of companies in the private sector. I accordingly propose to provide that all trust funds should be invested in specified modes, such as, Government securities, units of the Unit Trust of India,

deposits with scheduled banks, approved financial corporations, etc. Investment in immovable properties will, however, continue to be allowed. I am giving notice to all charitable and religious trusts to divest their share holdings and other investment in business concerns by 30th November, 1983. However, trusts will be allowed to keep shares in companies, which formed part of the original corpus as on June 1, 1973 and bonus shares received up to that date. Some trusts carry on business on commercial lines and derive income therefrom. There is no reason why such business income should not be brought to tax. I, therefore, propose that business income of all charitable and religious trusts including those which have hitherto been exempted by notification will be brought to tax with effect from assessment year 1984-85. Trusts having business income will also be required to conform to the new investment pattern if they wish to seek tax exemption in respect of their other income.

104. Hon'ble Members are no doubt aware that estate duty in respect of agricultural land is a State subject and that the Central has levied estate duty on agricultural land only by virtue of resolutions passed in this regard by State enabling the Union to do so. Our experience is that the valuation of agricultural land leads to administrative difficulties and litigation. The yield from this levy has also not been significant over the past several years. Moreover, after the abolition of wealth-tax on agricultural land, including plantations, there is little practical justification for continuing the levy of estate duty on agricultural land. I, therefore, propose to remove the levy of estate duty on agricultural land. Since the Estate Duty Act can be amended only after the necessary resolutions of State Legislatures, a Bill for giving effect to this proposal will be introduced later.

105. The revenue loss on account of the reduction in interest-tax will be Rs. 104 crores next year. Taking into account the estimated recoupment of part of this loss, my corporation tax proposals will yield Rs. 104 crores next year. My proposals in regard to income-tax will lead to net revenue accrual of Rs. 25.6 crores to the Centre next year and a loss of Rs. 28 crores to the States.

106. I turn now to my proposals in the area of indirect taxation. Mr. Speaker, Sir, the House is aware that for some years now our balance of payments has been under strain. Despite this we have sought to maintain an import regime which provides adequate access to imported inputs such as raw material and capital goods to the priority sectors. At the same time, I would not like that our policies should be taken advantage of by exporters abroad facing difficult market conditions by selling unduly cheap in the Indian market to the detriment of Indian industry. I believe we should use the instrument of customs duties not only to help revenue collection but to support our balance of payments and industrial expansion. In framing my proposals I have also tried to minimise tax avoidance and evasion and taken care to see that the measures would not spur inflation.

107. Taking customs duties first, my principal proposal is to continue the auxiliary duties of customs first imposed from 1973 and since renewed annually. I propose also to raise with certain exceptions the present effective rates by 5 percentage points. The statutory rate of auxiliary duty is proposed to be kept at 50 per cent, and the maximum

effective rate at only 35 per cent. The cushion of 15 per cent will help us take care of any need for higher duty levels which may become necessary for reasons such as support for indigenous production. Newsprint and cryde petroleum would not be subject to the increase in auxiliary duty. The existing full exemption from auxiliary duties on essential items like fertilizers, kerosene, high speed diesel oil would be continued. The revenue gain as a result of this proposal would be Rs. 254.5 crores in a full year.

108. My next proposal relates to chemicals. This group of commodities is in general subject to a basic rate of customs duty at 60 per cent ad valorem. With the significant fall in the international prices of chemicals, I believe it would be appropriate to raise the tariff rate to 100 per cent ad valorem and the general effective rate to 70 per cent ad valorem. Tariff rates of 40 per cent and 100 per cent applicable to certain groups of chemicals are also being raised on the same lines. However, pharmaceutical chemicals and drugs, insecticide, pesticide and fungicide chemicals, fertilizers, tanning substances, etc. have by and large been kept out of the purview of the proposed increase. This measure will yield Rs. 37.5 crores in a full year.

109. I also propose to raise the effective basic import duty on zinc metal from 45 per cent to 55 per cent ad valorem and that on lead metal from 40 per cent to 55 per cent ad valorem. The existing partial exemption from countervailing duty on lead scrap and waste is also proposed to be withdrawn. These measures will yield additional revenue of Rs. 12.8 crores in a full year, and would also improve the financial viability of indigenous producers.

110. For the benefit of our electronic industry, the existing concessional basic import duty of 45 per cent ad valorem is proposed to be extended to four more items of raw materials and components. Besides, the concessional basic import duty of 35 per cent ad valorem in respect of capital goods is proposed to be extended to 14 more items. These steps would cost the exchequer Rs. 1.22 crores in a financial year.

111. Another concession relates to bonafide gifts received from abroad by post or air freight. The existing duty-free value limits for such gifts were fixed in 1968. I propose to raise the duty-free limit for bonafide gifts of food articles and medicines imported by post or as air freight, and other items imported by post to Rs. 200. This liberalisation, I am sure, would be welcomed by those who receive genuine gifts from their friends and relatives abroad. The revenue sacrifice would be Rs. 3.71 crores in a full year.

112. I also propose to rationalise and liberalise the provisions relating to import duties on articles of baggage which are brought by passengers returning to India. The present duty-free limit for baggage is Rs. 1000 fixed in 1978. I propose to raise this limit to Rs. 1250 for adults with corresponding increase for minors and other categories of passengers. Keeping in mind the needs of Indian workers abroad who are generally engaged on contracts of one year and who then return to India, I propose a higher duty-free allowance of Rs. 5000 for them for used household effects with some exceptions. The rate of basic duty on the first dutiable value slab will remain 130 per

cent, while on the value in excess of first dutiable slab it is being reduced from 300 per cent to 200 per cent ad valorem except for a few articles. Auxiliary duty will be in addition. The list of articles of baggage in respect of which duty-free entry will not be admissible is being shortened. I am sure these measures would reduce the rigours of customs clearance for incoming passengers. I do not anticipate any fall in revenue because of this liberalisation.

113. A few amendments to the Customs Act, 1962 are also proposed to streamline the working of the department in the field and to enable more efficient revenue collections. The changes relate mainly to the setting up of the Inland Container Depots and provisions relating to warehousing and drawback. A fair amount of customs revenue remains blocked because of inordinately long warehousing of goods and it is therefore proposed to reduce the warehousing time to one year in the case of non-consumable stores and to three months for other goods. As a measure to expedite drawback payments, it is being provided that for claiming drawback it would be sufficient if the goods are entered for export to a place outside India. The minimum amount for which a claim for drawback would be entertained is also being raised from Rs. 5 to Rs. 50.

114. Power is also proposed to be taken under the Customs Act for the Government to fix effective rates of duty on a basis different from the one spelt out in the tariff. Thus, if the tariff rate of duty is on ad valorem basis, the Government would have the power to fix effective rates of duty on the basis of weight, volume, etc.

115. Sir, coming now to my proposals in respect of excise duties my objective has been primarily to mop up windfall gains where I believe they exist, and to limit the incidence of additional levies on individual items to relatively small proportions. I have also kept to the fore the important objective of promoting the small scale sector which has been a nursery for entrepreneurship in the country and has also helped to diffuse the concentration of economic power.

116. I propose to continue the levy of special excise duties in 1983-84 at the existing rates.

117. Cement prices, as Hon'ble Members are aware, have been ruling high in the markets. To mop up undue profits, I propose to raise the basic excise duty on cement from Rs. 135 to Rs. 205 per tonne for the commonly used variety of cement. The basic excise duty on cement produced in mini-cement plants will also go up from Rs. 100 to 170, thus maintaining the existing duty differential of Rs. 35 per metric tonne in favour of the mini plants. The revenue gain would be Rs. 182 crores in a full year by way of Central excise duties and Rs. 6 crores by way of countervailing duties on imports of cement.

118. Central Excise Tariff item 68 covers a miscellany of goods not elsewhere specified in the Tariff. The rate of duty has been unchanged at 8 per cent ad valorem from 1979. I propose to raise the rate now to 10 per cent ad valorem. This measure is likely to yield an additional revenue of Rs. 120 crores by way of Central excise duties and Rs. 60 crores by way of countervailing duties in a full year. This increase would be basically on finished goods since the raw materials and manufactured inputs

covered by this tariff item will continue to be eligible for duty credit as at present. I have taken care to protect the small scale sector, as I will be mentioning later.

119. I have also proposed a package of measures relating to man-made fibres, blended yarns and fabrics. Honble Members would recall that in my Budget last year several duty changes were made to encourage the production of blends with the desirable proportions of polyester. As a further measure in this area, I now propose to give a competitive edge to polyester-cotton blended fabric vis-à-vis polyester-viscose blended fabrics. The incidence of basic and additional duty on polyester-cotton fabrics containing more than 40 per cent but less than 50 per cent polyester is proposed to be reduced from 15 per cent ad valorem to 6.5 per cent ad valorem. These concessional rates would not, however, apply if polyester filament yarn is used. The overall incidence of duty on cotton yarn containing more than 40 per cent but less than 50 per cent polyester is also being reduced from Rs. 11.25 to Rs. 7.5 per kilogram. The revenue sacrifice entailed in these changes is Rs. 19.40 crores in a full year.

120. The effective duty on viscose staple fibre is being raised from Rs. 4 per kilogram to Rs. 5 per kilogram. further, to discourage the increasing imports of this fibre, I propose to raise the import duty on ordinary viscose staple fibre from 30 per cent to 40 per cent ad valorem and on improved varieties of viscose staple fibre also to 40 per cent ad valorem. The revenue gain will be Rs. 5.6 crores.

121. In the case of imported polyester fibre, considering the gap between its landed cost and domestic prices, it is proposed to raise the effective duty on polyester staple fibre by Rs. 9 per kilogram. This would yield Rs. 9 crores in a full year.

122. Polyester filament yarn is used in comparatively higher priced fabrics and I propose to raise the effective excise duty by Rs. 7.50 per kilogram on filament yarns of textile applications. This increase would be equally incident on imported filament yarn by way of higher countervailing duty. The increase would not be applicable to polyester filament yarn of 750 deniers and above which goes into industrial applications. The revenue gain in a full year would be Rs. 22.5 crores by way of excise duties and Rs. 5.6 crores by way of countervailing duties.

123. In step with the above increase, I also propose to raise the effective duty on nylon filament yarn of textile deniers by the same margin. The additional revenue yield will be Rs. 15.5 crores by way of Central excise duties and Rs. 50 lakhs by way of countervailing duties in a full year.

124. As a measure to combat tax avoidance I propose to change the basis of duty from ad valorem to ad valorem-cum-specific rate or specific rate on a few commodities. In respect of paper, while adopting an ad valorem-cum-specific rate. I propose to fix a uniform rate for printing, writing and most of the other varieties of paper and paper board. The effective basic duty for kraft paper will be 10 per cent ad valorem plus Rs. 1810 per metric tonne and for most of the other varieties of paper and paper board, 10 per cent ad valorem plus Rs. 1430 per metric tonne. The existing concessional basic rate of 5 per cent ad valorem in respect of white printing paper supplied to

Director General, Supplies and Disposals or for educational purposes would, however, continue.

125. I have also reviewed the present concessions available to small paper mills. The linking of the concession enjoyed by this sector to the installed capacity of a plant has been posing some practical problems. I, therefore, propose to rationalise the concessions to this sector on the basis of quantum of clearance in a financial year. The extent of exemption is also being suitably modified which should encourage the small paper mills to increase their production substantially. Rates of duty for paper manufactured in such paper mills using unconventional raw material will be Rs. 560, Rs. 900 or Rs. 1120 per tonne depending on whether the clearances of paper and paper board from such paper mills in the preceding financial year did not exceed 3000 tonnes, 7500 tonnes or 16500 tonnes respectively.

126. In regard to aerated waters it is proposed to fix specific rates of duty to replace the existing ad valorem rates. The effective basic duty for a bottle of 200 milliliters will be, 5 paise for soda and 30 paise for others. The concessions available to small scale manufacturers would continue.

127. The present ad valorem rate in respect of motor cars is being converted into ad valorem-cum-specific rate. The effective rates would be based on the engine capacity and would be different for petrol driven and diesel driven cars.

128. In the case tyres used in two-wheeled vehicles and tractors and tyres of specified sizes for trailers, the present basic tariff rate of 60 per cent is proposed to be reduced to 25 per cent which is the level of the present effective rates of duty.

129. The House may recall that in November last the concessional rates of duty on cigarettes were withdrawn and cigarettes were made liable to pay statutory rates. The revenue realisations had been affected inter alia on account of disputes over the method of arriving at the assessable value. With a view to ending the room for uncertainty once for all I propose to fix specific rates of duty in respect of cigarettes. These rates of duty would be linked to their retail sale prices printed on the cigarette packs. Keeping in view the fact that the consumption of cheaper cigarettes is large, I have also sought to have a graded levy based on retail prices. The duty now proposed will, at the lowest slab, be Rs. 35 per thousand cigarettes. I expect that this measure would help the Government to realise the revenue expected from this item.

130. All these anti-avoidance measures would help secure revenue of the order of Rs. 50 crores which otherwise might have been avoided.

131. There have been strong representations from many quarters that the existing scheme of concession in excise duty for the small scale sector hampers continuous growth and should be liberalised. I have reviewed the matter. Under the general scheme applicable to 70 specified groups of commodities at present, manufacturers are eligible to get full duty exemption upto first clearances of Rs. 7.5 lakhs and the concessional rate of 75 per cent of the duty payable on clearances in excess of Rs. 7.5 lakhs but upto

Rs. 15 lakhs. I propose to raise the upper limit from Rs. 15 lakhs to Rs. 25 lakhs. At the same time, I propose to reduce the limit of full exemption from Rs. 7.5 lakhs to Rs. 5 lakhs. The clearances in excess of Rs. 5 lakhs upto Rs. 25 lakhs would, however, enjoy a concessional rate of duty of 75 per cent of the normal duty payable.

132. Two commodity groups, namely cosmetics and toilet preparations, and the other, refrigerating and air-conditioning appliances and machinery and their parts bear high rates of excise duty and will be deleted from the general scheme. An alternative exemption scheme has been provided for these items under which small manufacturers with total clearances upto Rs. 2.5 lakhs would be completely exempt from payment of duty and those with turnover upto Rs. 15 lakhs would pay duty at half the normal rate on the entire clearance.

133. As regards the exemption available to the small scale manufacturers of goods falling under Tariff Item 68, I propose to raise the eligibility limit of Rs. 30 lakhs by way of value of clearances in the previous year to Rs. 40 lakhs. This measure would help the small scale units to avail of the benefit of exemption while expanding their turnover. With the increase in the rate of duty from 8 per cent to 10 per cent which I mentioned earlier, the amount of the new concessions can go up to Rs. 3 lakhs against Rs. 2.4 lakhs till now.

134. For both the schemes, I propose to exclude the clearances of exempted goods, other than those exempted under small scale exemptions, from the computation of value of clearances for the purpose of determining the eligibility as well as availment of exemption from duty. The net revenue effect of all these concessions for the small scale sector will be a loss of Rs. 5 crores in a full year.

135. As part of the 1982 Budget, I had announced an excise duty relief scheme for encouraging higher production in respect of certain specified commodity groups. I propose not only to continue the scheme but also enhance the relief in duty for excess clearances. Under the existing scheme, there is, for excess clearances, a relief of 20 per cent of duty for items falling in certain duty rate groups and 10 per cent for those falling in other such groups. I propose to provide incentive in two slabs instead of the present single slab. I also propose to increase the present incentive of 20 per cent and 10 per cent respectively to 30 per cent and 15 per cent for the first slab of excess clearances and to 40 per cent and 20 per cent for the subsequent slab. I am hopeful that industry would take advantage of this liberalisation and step up production.

136. I have also proposed a few changes which would benefit State Governments. The first is in relation to coated fabrics, both cotton and man-made and stocked fabrics where additional excise duty (in lieu of sales tax) of 5 per cent ad valorem is being proposed in addition to the duty on base fabrics. This measure would net an additional revenue of Rs. 3.4 crores in a full year. The other proposal relates to sandalwood oil in respect of which all extent exemptions are being withdrawn. The net gain from this proposal is Rs. 30 lakhs in a year.

137. I now come to changes which do not involve any significant revenue. I propose a few changes in the tariff descriptions relating to iron and steel items which would align the Central Excise Tariff, as far as these items are

concerned, with the Indian Customs Tariff. The principles of classification hitherto adopted through executive instructions are being incorporated in the tariff entry itself. The tariff entries relating to iron and steel would be spelt out on a more scientific basis and the problems encountered in the matter of charging countervailing duty would also be reduced considerably. These changes would, however, be brought into effect from a subsequent date after the necessary groundwork. Till then, the present effective rates of duty would continue.

138. Lest this litany of measures give the impression that the Finance Minister's proposals only relate to raising revenue, let me add that where appropriate I have tried, as I will be announcing now, some concessions in excise duties.

139. Sugar is an important item in the family budget. I propose to reduce the duty on both 'levy' and 'non-levy' sugar. The present ad valorem rates are being replaced by specific rates, that is 38 paise per kilogram on 'levy' sugar and 50 paise per kilogram on 'non-levy' sugar. The revenue sacrifice will be of the order of Rs. 21.02 crores in a full year. I have, however, taken special care to see that the amount due to the States from additional excise duty in lieu of sales tax on sugar is not affected.

140. Housewives in India, as elsewhere, have been complaining for some time about the rise in their expenses. As a measure of economising on their fuel bills without affecting the nutritional and, hopefully, the gastronomic value of what they cook, I propose to exempt totally pressure cookers from excise duties. They would now find someone else in their kitchens letting off steam.

141. With the same intention of promoting fuel economy, I propose also to exempt fully from excise duty fuel efficient kerosene stoves.

142. The effective basic rates of excise duty on electric bulbs upto 60 watts and fluorescent tubes are now 10 per cent ad valorem and 30 per cent ad valorem respectively. As a measure to reduce the prices of these items, and thus help in the effort to shed more light at lesser cost, I propose to exempt fully the former from excise and reduce the basic duty on the latter from 30 per cent to 20 per cent ad valorem.

143. In consideration of the potential of multi-axled vehicles for fuel savings, I propose to reduce the effective basic duty on them from 15 per cent to 10 per cent ad valorem.

144. For the benefit of farmers, who use these fertilizers, I propose to fully exempt ammonium sulphate and calcium ammonium nitrate from excise duty, as also agricultural grade pyrites used for reclamation of alkaline soils.

145. Aluminum pipes used in sprinkler equipment for irrigation, which at present bear a basic duty of 16 per cent ad valorem, will also be fully exempted. Another proposal is for exemption from excise duty of internal combustion engines for agricultural sprayers, and also for powered cycles.

146. One of the factors leading to higher prices of prepared or preserved foods, and food products is the cost of the metal containers used in their packaging. I propose to exempt these items from that part of excise duty as is relatable to the cost of such containers. This should bring about a reduction in the price of these foods to the consumer.

147. Skimmed milk powder sold in packs upto 1 kilogram is also being fully exempted from duty as a measure to reduce its prices to consumers.

148. I also propose to fully exempt from duty some specified items of hospital furniture which should reduce the cost of acquiring them for the hospitals.

149. These duty concessions would cost the exchequer Rs. 35.02 crores in a full year.

150. There are some other proposals in respect of customs and excise duties which are relatively minor. I do not wish to take the time of the House over them.

151. The proposal I have presented will yield revenue of Rs. 409.00 crores in a full year in Central excise duties and Rs. 397.96 crores in custom duties. The concessions and reliefs amount to Rs. 83.58 crores on the Central excise side and Rs. 4.93 crores on the custom side. The net yield is therefore, Rs. 325.42 crores from Central excise duties and Rs. 393.03 crores from customs duties. The accrual to the Central Exchequer in a full year will be Rs. 589.71 crores and the share of the States will be Rs. 128.74 crores.

152. Where the changes are to be made by notifications effective from 1st March, 1983, copies thereof will be laid on the Table of the House in due course.

153. In framing the Budget proposals, I have been greatly helped by the observations and recommendations in reports of Parliamentary Committees and also the reports made so far by the Economic Administration Reforms Commission. My proposals reflect these recommendations, wherever feasible and appropriate, but I must add that it has not been possible for the Government to take decisions finally on all the recommendations in the reports. A number of them on important matter, such as a Tribunal for valuation of urban properties, will be processed for a Direct Taxes Amendment Bill, the preparation of which will be taken in hand.

154. This year I have not much to say on behalf of my Hon'ble colleague, the Minister of Communications as he has already taken care of himself. The postal services are being expanded every year to reach more and more people.

Presently there are over 1,41,000 post offices, and an employee strength of about 5.8 lakhs including extra-departmental staff. With a view to meeting part of the increasing operating costs, it has become necessary to revise the postal tariff. While I do not propose to touch post-cards and letter-cards, the tariff in respect of parcels is proposed to be increased to yield Rs. 12 crores in a full year and Rs. 10 crores in 1983-84. A Memorandum showing the proposed tariff is being circulated along with the Budget documents. The changes will take effect from a date to be notified after the Finance Bill is passed by Parliament.

155. I had earlier mentioned that the budgetary deficit at the existing rates of taxation would be Rs. 2250 crores. The proposed tax measures, taken together with the reliefs and concessions, are estimated to yield net additional revenue of Rs. 615.31 crores to the Centre and Rs. 100.74 crores to the States during 1983-84. Besides, I am taking credit for Rs. 135 crores as receipts from the new Bond to be issued in terms of the approved investment to obtain exemption from capital gains tax. After setting off the receipt of Rs. 55 crores from the existing National Rural Development Bonds already included in the Budget, the net yield on this account would be Rs. 80 crore. The budgetary deficit would thus get reduced to Rs. 1555 crores, which Hon'ble Members would agree would not put undue strain on the economy.

156. Mr. Speaker, Sir, there are no easy answer or shortcuts to development problems faced by India. Whether we, as a nation, succeed or fail must ultimately depend on the quality of our economic management and the cooperation of people. It is true that we have been able to maintain price stability despite a setback in agriculture in the current year, increase our national income by about 5 per cent per annum in the last three years and show some improvement in our balance of payments despite an unfavourable international environment. These achievements, however, must not lull us into a false sense of economic well-being. The road ahead is long arduous. Given the resilience and dedication of our people, we can face the future with hope and confidence.

157. Sir, I now commend the Budget to the House.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.